राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 04 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-12 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, नहीं चल सका प्रश्नकाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक (मेमोयर) को लेकर जारी विवाद के चलते विपक्षी दलों ने सदन की कार्यवाही बाधित कर दी। हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष नरवणे की किताब से जुड़े मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा था। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश की और बार-बार विपक्षी सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटने और सदन को चलने देने की अपील की। हालांकि, उनकी अपील का विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा

और शोर-शराबा लगातार जारी रहा।

स्थिति नियंत्रित न होते देख स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी और सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रश्नकाल ठप रहने से कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा नहीं हो सकी। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार स्पीकर ओम बिरला पीठ पर मौजूद नहीं थे। उनकी जगह स्पीकर पैनल के सदस्य कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने सदन को बताया कि विभिन्न मुद्दों पर कई सांसदों की ओर से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं, लेकिन स्पीकर की ओर से किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है।

हालांकि कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी सदन का माहौल पूरी तरह शांत नहीं हो सका। विपक्ष लगातार नरवणे की किताब से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा, जबकि सरकार का रुख रहा कि अप्रकाशित और असत्यापित सामग्री के आधार पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख की किताब का संदर्भ प्रस्तुत करने को लेकर सोमवार से ही संसद में राजनीतिक टकराव जारी है। विपक्ष इसे सरकार द्वारा तथ्यों को दबाने का प्रयास बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय नियमों से जुड़ा मामला बता रहा है। हंगामे के चलते बजट सत्र की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है।

युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के 13वें सीएम, भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। अब राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक कुकी समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इस दौरान मणिपुर के विधायक दल का नेता चुनने के लिए नियुक्त सेंट्रल ऑब्जर्वर तरुण चुग, संबित पात्रा और मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। मणिपुर से एनडीए के करीब 20 विधायक रविवार रात को दिल्ली पहुंचे थे। वहीं अन्य विधायक सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी पहुंचे। 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद, 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है।

अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई को सौंपी

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने अपने हाथ में ली है। साथ ही, मामले में दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम ब्रांच ने एक वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की टीम के दो सदस्य उत्तराखंड पहुंचे ताकि लड़की की हत्या से जुड़े कथित वीआईपी एंगल की डिटेल में जांच कर सकें। यह केस तब सुर्खियों में आया जब भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप और वीडियो सामने आए। एक फेसबुक लाइव के दौरान, सनावर ने हत्या में एक वीआईपी के कथित तौर पर शामिल होने का जिक्र किया, जिससे नया विवाद और बहस शुरू हो गई। इन घटनाओं से राजनीतिक तनाव बढ़ा और विपक्षी पार्टियों और कई संगठनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग फिर से शुरू कर दी।

ट्रेड डील खेती-किसानी और उस पर निर्भर 70 फीसदी आबादी के साथ धोखा

-अखिलेश बोले- भाजपाई और उनके संगी-साथी पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के लिए खोलना देश की खेती-किसानी और उस पर निर्भर करीब 70 फीसदी आबादी के साथ धोखा है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी ने फिर किया 'किसानों' पर वार।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार दे जवाब, क्या है दबाव में भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना, हमारे देश की खेती-किसानी पर जिंदगी बसर करने वाली 70फीसदी आबादी के साथ धोखा है। भाजपाई और उनके संगी-साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है।

उन्होंने कहा कि इस डील से केवल किसान ही नहीं, निम्न मध्यवर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मुनाफाखोरी व बिचौलियों की एक नई जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने-पीने की सब चीजें और महंगी हो जाएंगी। साथ ही बीजेपी इन कंपनियों से चंदा वसूली भी करेगी, जिससे खाद्य व कृषि उत्पाद और भी महंगे हो जाएंगे। इससे धीरे-धीरे हमारे किसानों की खेतीबाड़ी और आय कम हो जाएगी और वो मजबूर होकर अपनी जमीन अमीरों व कारपोरेट को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। जमीनों पर कब्जा करना ही भाजपाई और उनके संगी-साथियों का मकसद है।

लोकसभा में 'यार' शब्द पर हंगामा : राहुल गांधी ने संस्मरण का दिया हवाला, स्पीकर ने जताया ऐतराज

नई दिल्ली। अगस्त 2020 के लद्दाख विवाद को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही तीखी बहस चल रही थी। इसी बीच, लोकसभा में एक नया हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्ष की ओर से किसी सदस्य ने कथित तौर पर 'यार' शब्द का प्रयोग किया। हाउस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस सांसदों को फटकार लगाई। उन्होंने इसे असंसदीय और आपत्तिजनक बताया, हालांकि कांग्रेस सांसदों ने इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने विपक्ष के नेताओं से सख्ती से कहा, 'आप चेयर को यार नहीं कह सकते हैं।' इससे पहले, सुबह से सदन की कार्यवाही में रुकावट के बाद दोपहर 2 बजे जब लोकसभा फिर से शुरू हुई,तो सदन में काफी हंगामा और शोर-शराबा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज नरवणे की एक किताब (जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है) से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करना चाहते थे। हालांकि, हाउस चेयरमैन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि जानकारी का सोर्स साबित करने के बावजूद उन्हें हाउस में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि, चेयर ने उनकी दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रूल 239 के तहत, स्पीकर ने एक ऐसा फैसला दिया है जो हाउस के सदस्यों को बिना वेरिफाइड या अस्पष्ट तथ्यों का जिक्र करने या उनके बारे में बोलने से रोकता है। नेता प्रतिपक्ष ने अपना आरोप जारी रखते हुए कहा कि वह सिर्फ लद्दाख में उठाए गए मुद्दे और प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, यह उठा रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत न मिलने का विरोध करते हुए कहा, 'हमारे प्रेसिडेंट का भाषण इस बारे में था कि भारत को किस रास्ते और दिशा में जाना चाहिए। ग्लोबल स्टेज पर, मुख्य मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच टकराव है। यह हमारे स्ट्रेटेजिक हितों के लिए ज़रूरी है। मुझे इसे उठाने से क्यों रोका जाना चाहिए?'

लोकसभा में पीठासीन की तरफ पेपर उछालने वाले 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। उनके इतना कहते ही संसद में मौजूद एनडीए सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं विपक्ष का नेता हूं। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। मैं बस बता रहा हूं की चाइना-इंडिया के बीच में क्या हुआ। पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक शहीद हुए। वहीं हंगामे के दौरान पीठासीन की तरफ पेपर उछालने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इसमें अमरिंद सिंह राजा वडिंग, प्रशांत परोले, एस वेंटकटरमण, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिबी ईडन, गुरजीत औजला और डीन कोरियोकोज शामिल हैं। उधर, राहुल गांधी के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डी एम कातिर आनंद ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से इंकार किया। इसके पहले लोकसभा में स्पीकर ने दूसरे सांसद को बोलने को कहा। स्पीकर ने राहुल गांधी से कहा कि मैंने बार-बार नेता विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने को कहा है। लेकिन वे बोलना नहीं चाहते हैं। सदन में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते पर बात करना जरूरी है। इसके बाद कार्यवाही 3 बजे स्थगित हो गई।

भारत के नियम नहीं मानने तुम्हें... देश छोड़कर चले जाओ

सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सएप को फटकारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सएप को फटकार लगाकर कहा है कि कोई भी कंपनी डेटा शेयरिंग के नाम पर इस तरह से लोगों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर भारत के नियम नहीं मानने हैं, तब तुम्हें देश छोड़कर निकल जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेटा और वॉट्सएप ने कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें उनपर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि 9 फरवरी को मामले में अंतरिम आदेश पारित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में निजता के अधिकार की सख्ती से रक्षा की जाती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि लोगों उन्हें

समझ ही नहीं पाएंगे और ये कंपनियां उनका डेटा चोरी करती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों को उन उपभोक्ताओं का डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देगा जिनके साथ असमान समझौते किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पक्षकार बनाकर कि वह नौ फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगा।

संसद में मोदी के खिलाफ लगे नारे, सदन के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन

-विपक्ष कर रहा अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर चर्चा की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर संसद के बजट सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस समझौते पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की।

बजट सत्र के पांचवें दिन मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन महज आठ मिनट के भीतर ही शोर-शराबे के चलते सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोपहर में जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी हालात नहीं सुधरे। सदन केवल 13 मिनट ही चल सका और विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि नारेबाजी नियमों के खिलाफ है और सदन की गरिमा बनाए रखी जाए, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा।

राज्यसभा में भी हंगामा और वॉकआउट

राज्यसभा में भी विपक्ष ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और आरोप लगाया कि इस समझौते से भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। खास तौर पर अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारत में आयात पर ड्यूटी घटाकर शून्य करने की संभावित बात पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो सस्ते अमेरिकी उत्पादों से घरेलू किसानों को भारी नुकसान होगा।

ट्रेड डील के खिलाफ सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन

संसद के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी विपक्षी सांसदों

ने ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर भारतीय किसानों के साथ 'विश्वासघात' करने का आरोप लगाया और कहा कि बिना संसद में चर्चा कराए इतना बड़ा फैसला लेना गलत है।

एसआईआर 'पीड़ितों' को अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया जा रहा : ममता

-पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से प्रभावित लोगों को अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया जा रहा। बनर्जी ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया। बंगाल में एसआईआर पीड़ितों के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारे पीछे बैठे सभी लोग एसआईआर के पीड़ित हैं। मैं यहां लाखों लोगों को ला सकती थी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि वे एसआईआर पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका नहीं दे रहे हैं।

ममता बनर्जी सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंची थी, लेकिन विरोध जताते हुए बैठक से बीच में ही बाहर निकल गईं। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रतिनिधिमंडल का अपमान हुआ है। उन्होंने आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। एसआईआर के समय पर सवाल उठाते हुए बनर्जी ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह प्रक्रिया केवल विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में ही क्यों की जा रही है, भाजपा शासित असम में क्यों नहीं, जहां चुनाव होने हैं। बनर्जी ने पूछा कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है? क्या बिना किसी योजना के इसे 2-3 महीनों के भीतर करना संभव है?

मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला: टैक्सींग के दौरान एअर इंडिया और इंडिगो विमानों के विंग्स टकराए, सभी यात्री सुरक्षित

मुम्बई (एजेंसी)। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब एअर इंडिया और इंडिगो के विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई। विमानों के विंग्स आपस में टकरा गए। घटना उस वक्त हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं।

एअर इंडिया की फ्लाइट ढ्ढ 2732 मुंबई से कोयंबटूर जाने के लिए टेक-ऑफ से पहले पुशबैक की प्रक्रिया में थी। इसी दौरान इंडिगो की फ्लाइट 6श्व 791, जो

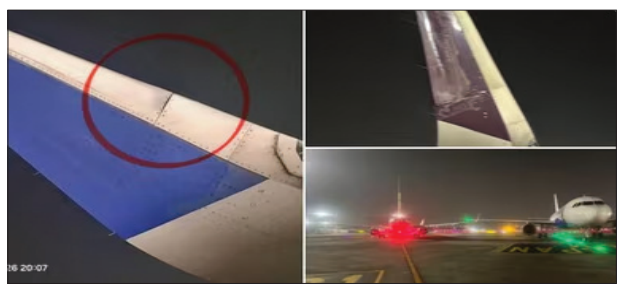

हैदराबाद से मुंबई पहुंची थी, लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी। इसी दौरान दोनों विमानों के विंगटिप आपस में टकरा गए। एअर इंडिया की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 3 फरवरी को मुंबई से कोयंबटूर जाने वाली फ्लाइट ढ्ढ 2732 में देरी हुई, क्योंकि जिस विमान को इस उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जाना था, वह टैक्सीवे पर खड़े दूसरे एयरलाइन के विमान से संपर्क में आ गया। एअर इंडिया के बयान के अनुसार, दोनों विमानों के विंग्सटिप आपस में टकराए, जिससे एअर इंडिया के विमान के विंगटिप को नुकसान पहुंचा। एअर इंडिया ने बताया कि एहतियातन विमान को आगे की तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया और ग्राउंड स्टाफ यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है।

बोइंग 787 की उड़ान पर फिर सवाल: एअर इंडिया के विमान में 'फ्यूल कंट्रोल स्विच' में खराबी, जांच तेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। एअर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में एक बार फिर तकनीकी खामी सामने आई है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु तक उड़ान भरने वाले विमान (फ्लाइट नंबर एआई-132) में फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की शिकायत पायलट ने दर्ज कराई है। विमान में 200 से अधिक यात्री सवार थे। सोमवार सुबह बेंगलुरु में सुरक्षित लैंडिंग के बाद पायलट ने डिफेक्ट लॉग बुक में उल्लेख किया कि बाएं इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच 'रन' पोजिशन से फिसलकर 'कट-ऑफ' की ओर जा रहा था और अपनी जगह पर लॉक नहीं हो पा रहा था।

फ्यूल कंट्रोल स्विच का इस्तेमाल इंजन को स्टार्ट और बंद करने के लिए किया जाता है। उड़ान के दौरान इसमें गड़बड़ी होना गंभीर सुरक्षा जोखिम माना जाता है। पायलट की रिपोर्ट मिलते ही एअर इंडिया ने संबंधित विमान को तुरंत ग्राउंड कर दिया और जांच के लिए मूल उपकरण निर्माता बोइंग को शामिल किया। साथ ही इस मामले की जानकारी नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को भी दे दी गई है।

एअर इंडिया ने बयान में कहा कि डीजीसीए के निर्देश पर उसके पूरे बोइंग 787 बेड़े के फ्यूल कंट्रोल स्विच की पहले ही जांच की जा चुकी है, जिसमें किसी तरह की खामी नहीं पाई गई थी। हालांकि ताजा घटना के बाद जांच प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। इस बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने दावा किया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी की समस्या लंदन हीथ्रो पर ही सामने आ गई थी। संगठन ने जून 2025 में हुए एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 हादसे का हवाला देते हुए ड्रीमलाइनर विमानों की इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गहन जांच की मांग दोहराई है।

गैर-लाभकारी संस्था सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने भी चेतावनी दी है कि इंजन स्टार्ट के दौरान स्विच का लॉक न होना, कुछ परिस्थितियों में उड़ान के दौरान इंजन बंद होने का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रही एअर इंडिया की बोइंग 787-8 फ्लाइट एआई-171 टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में दोनों इंजनों में ईंधन आपूर्ति अचानक बंद होने की बात सामने आई थी। इस हादसे की जांच अभी जारी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

विकसित भारत बनाने में भारतीय रेल परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार

रेलवे विद्युतीकरण भी इस बजट का एक मजबूत स्तंभ है। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय रेल नेटवर्क पूर्णतः विद्युतीकृत होकर ऊर्जा दक्ष, तेज,सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बने। विद्युतीकरण से परिचालन लागत घटेगी,माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत होगा। रेलवे की गति केवल ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ाएगी,बल्कि यह भारत की आर्थिक गति को भी तेज करेगी। रेल बजट 2026-27 का सबसे प्रत्यक्ष और जनसरोकार से जुड़ा पक्ष अमृत भारत स्टेशन योजना है। देशभर में सैकड़ों रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।

(लेखक- विनोद कुमार सिंह)

– मोदी सरकार के आम बजट मे मिशन और केन्द्रीय रेल अश्विनी वैष्णव का ऐतिहासिक विजन में भारतीय रेल देश की आर्थिक रीढ़ व विकसित भारत बनाने में मिल का पत्थर साबित होगा वैश्विक मानचित्र पर आए दिनों चर्चा व चिन्तन भारत का होना आम बात है, लेकिन इन दिनों आम बजट मे रेल मंत्रालय को आवांटित राशि को ले चहूँ दिशाओं में विकाश की तेज रफ्तार व सीटी सुनाई पड़ने लगी है। केन्द्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है और यह बजट केवल सरकार के आय-व्यय का लेखा नहीं,बल्कि भारत के भविष्य का वह निर्णायक दस्तावेज है जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को नई शक्ति देता है। इस बजट का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि भारतीय रेल को केन्द्र में रखकर मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माण की गति को और तेज करने का स्पष्ट संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 卐विकसित भारत मिशन卐 और केन्द्रीय रेलमंत्रीअश्विनी वैष्णव का आधुनिक रेलवे विजन अब कागजों की योजना नहीं,बल्कि बजट की ठोस घोषणाओं और रिकॉर्ड निवेश के माध्यम से यथार्थ की धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। भारतीय रेल आज अपने यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाने वाली व्यवस्था नहीं रह गई, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़,उद्योगों की जीवनरेखा,कृषि बाजारों की शक्ति और रोजगार सृजन का सबसे बड़ा इंजन बन चुकी है। आप को मै स्पष्ट कर दुँ किवर्ष 26-बजट में भारतीय रेल को लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है,जो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार माना गया है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निवेश को देश की आर्थिक पटरी पर तेज रफ्तार विकास का विजय घोष कहा है। सर्वविदित रहे कि पिछले दशक में रेलवे में जिस स्तर पर परिवर्तन आया है,वह स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार,नई तकनीक का समावेश,स्टेशन पुनर्विकास,हाई- स्पीड रेल परियोजनाएँ और हरित ऊर्जा की दिशा में कदम- यह सब भारत को एक नई रेल क्रांति की ओर ले जा रहा है। रेल बजट 2026-27 का सबसे बड़ा आकर्षण सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा है। ये कॉरिडोर भारत के औद्योगिक केन्द्रों,व्यापारिक शहरों, कृषि उत्पादन क्षेत्रों और निर्यात हब को तेज गति से जोड़ेंगे। हाई-स्पीड रेल नेटवर्क केवल यात्रियों के समय की बचत नहीं करेगा,बल्कि यह निवेश आकर्षण,उद्योग विस्तार, पर्यटन विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के तीव्र उत्थान का माध्यम बनेगा। जब शहरों के बीच दूरी घटती है,तब व्यापार की गति बढ़ती है,नए रोजगार के अवसर पैदा होते है। इससे आर्थिक गतिविधियाँ कई गुना तेज हो जाती हैं। दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी- सिलीगुड़ी जैसे कॉरिडोर उत्तर भारत और पूर्वी भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। यह विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों का सबसे बड़ा संकेत है। इसी बजट में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना को आगे बढ़ाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। भारत अब केवल परंपरागत डीजल इंजनों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण अनुकूल,ऊर्जा दक्ष और भविष्य की परिवहन प्रणाली का प्रतीक हैं। इससे प्रदूषण घटेगा, ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत हरित परिवहन क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह वही सोच है जो विकसित राष्ट्रों की पहचान बन चुकी है। अब भारत भी उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना को भी बजट 2026-27 में नई ऊर्जा मिली है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और आधुनिक राष्ट्र निर्माण की पहचान बन चुकी है। बुलेट ट्रेन केवल एक रेल सेवा नहीं,बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, निवेश सामर्थ्य और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में इसका विस्तार भारत को हाई-स्पीड ट्रांसपोर्ट के वैश्विक मानचित्र पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। रेलवे विद्युतीकरण भी इस बजट का एक मजबूत स्तंभ है। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय रेल नेटवर्क पूर्णतः विद्युतीकृत होकर ऊर्जा दक्ष, तेज,सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बने। विद्युतीकरण से परिचालन लागत घटेगी,माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत होगा। रेलवे की गति केवल ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ाएगी,बल्कि यह भारत की आर्थिक गति को भी तेज करेगी। रेल बजट 2026-27 का सबसे प्रत्यक्ष और जनसरोकार से जुड़ा पक्ष अमृत भारत स्टेशन योजना है। देशभर में सैकड़ों रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशन अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक यात्री सुविधा केन्द्र,व्यापारिक गतिविधियों के हब और स्थानीय रोजगार के केन्द्र बनेंगे। छोटे शहरों और कस्बों में स्टेशन विकास से होटल,टैक्सी, दुकानें,स्थानीय हस्तशिल्प, खानपान उद्योग और पर्यटन व्यवसाय को नया जीवन मिलेगा। रेलवे स्टेशन अब विकास के प्रवेश द्वार बनेंगे। नई रेल लाइनों,डबलिंग, ट्रैक अपग्रेडेशन और फेट कॉरिडोर परियोजनाओं पर भी बजट में विशेष बल दिया गया है। माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे को आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बदला जा रहा है। इससे कृषि उत्पाद तेजी से बाजारों तक पहुँचेंगे,उद्योगों को कच्चा माल समय पर मिलेगा और निर्यात क्षेत्र को नई शक्ति मिलेगी। रेलवे विकास का अर्थ केवल यात्री सुविधा नहीं,बल्कि भारत के उत्पादन और व्यापार की क्षमता में क्रांतिकारी वृद्धि है। इस बजट का सबसे बड़ा सामाजिक

प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देगा। नई परियोजनाओं से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इंजीनियरिंग,निर्माण,तकनीकी सेवा,आईटी सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था,खानपान,पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ खुलेंगी। रेलवे परियोजनाएँ केवल सरकारी नौकरियाँ नहीं,बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करती हैं। राज्यवार आवंटन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि रेलवे विकास अब केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं,बल्कि पूरे भारत में संतुलित विस्तार का माध्यम बन चुका है। 2026-27 में महाराष्ट्र को लगभग 23,926 करोड़ रुपये,उत्तर प्रदेश को 20,012 करोड़ रुपये,गुजरात को 17,366 करोड़ रुपये,मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रुपये,पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपये, राजस्थान को 10,228 करोड़ रुपये,बिहार को 10,379 करोड़ रुपये,झारखंड को 7530 करोड़ रुपये,ओडिशा को 10,928 करोड़ रुपये और असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को 11,486 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि रेलवे विकास नीति में क्षेत्रीय संतुलन और व्यापक विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार जैसे राज्यों में यह निवेश विशेष महत्व रखता है,क्योंकि बीते वर्षों की तुलना में बिहार को कई गुना अधिक आवंटन मिला है। इससे राज्य में नई रेल परियोजनाएँ, स्टेशन विकास,पर्यटन कनेक्टिविटी और स्थानीय व्यापार को बड़ा लाभ होगा। मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी रेलवे निवेश में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है,जो इन क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता और रोजगार अवसरों को व्यापक बनाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष आवंटन इस बात का संकेत है कि सरकार सीमांत क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल बजट 2026- 27 वास्तव में मोदी सरकार की उस सोच का प्रतिबिंब है। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार माना गया है। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत मिशन अब रेलवे जैसी जीवनरेखा में हो रहे रिकॉर्ड निवेश से वास्तविकता बनता दिख रहा है। वैष्णव का विजन भारतीय रेल को आधुनिक,सुरक्षित,तेज, पर्यावरण अनुकूल और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में निर्णायक है।

भारतीय रेल आज नई पटरियाँ बिछा रही है, लेकिन उससे भी अधिक वह भारत के भविष्य की आर्थिक पटरी बिछा रही है। यह बजट आने वाले वर्षों में भारत को न केवल एक विशाल रेल नेटवर्क वाला देश बनाएगा,बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएगा जो गति, सुरक्षा,हरित ऊर्जा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए मानकों पर खड़ी होगी। विकसित भारत की ओर दौड़ती यह रेलगाड़ी अब रुकने वाली नहीं है,क्योंकि इसके पीछे राष्ट्र की आकांक्षा है,सरकार की प्रतिबद्धता है और भविष्य की अनिवार्यता है। *

मोदी सरकार के आम बजट मे मिशन और केन्द्रीय रेल अश्विनी वैष्णव का ऐतिहासिक विजन में भारतीय रेल देश की आर्थिक रीढ़ व विकसित भारत बनाने में मिल का पत्थर साबित होगा* भारतीय रेल अब केवल यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि भारत के उत्थान,रोजगार,व्यापार और वैश्विक शक्ति बनने की यात्रा का सबसे बड़ा वाहक बन चुकी है।

संपादकीय

सतही आरोपों की राजनीति

राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी। गलवान में चीनी सेना के साथ खूनी टकराव के मामले में तत्कालीन सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश का जैसा उल्लेख राहुल गांधी ने किया, उस पर हंगामा होना ही था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका वह उल्लेख कैसे कर सकते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन पर गलतबयानी का आरोप लगाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और वह चल नहीं सका। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके नेता को सदन में बोलने से रोका गया। हंगामे के पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उससे इतना तो स्पष्ट ही है कि वे यही सिद्ध करना चाहते थे कि मोदी सरकार ने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये पर साहस नहीं दिखाया। राहुल गांधी कितनी तैयारी से आए थे, इसका पता इससे चलता है कि वे संदर्भ तो गलवन का देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उल्लेख डोकलाम का किया। यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का डटकर मुकाबला करने से बचते हैं। वे मोदी सरकार को कमजोर दिखाने के लिए यह भी कहते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वे यहां तक कह चुके हैं कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी थी। इसके बाद भी वे यह समझने के लिए तैयार नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सतही आरोपों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब जानते हैं कि गलवन में चीनी सेना को करारा जवाब मिला था और इसी कारण वह वार्ता की मेज पर आया और लद्दाख में कई इलाकों में यथास्थिति कायम हो पाई। इसे पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे भी एक नहीं कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। जहां तक उनकी पुस्तक की बात है, तथ्य यही है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने उसके प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है। यह भी एक तथ्य है कि जिस पत्रिका ने इस पुस्तक के कथित अंश छापे हैं और उनकी अपने हिसाब से व्याख्या की है, वह आधे-अधूरे तथ्यों के साथ सनसनी फैलाने के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी।

कैंसर मौन महामारी, जागरूकता ही है सबसे बड़ा हथियार

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

(विश्व कैंसर दिवस (4 फरवरी) पर विशेष)

लोगों को कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 4 फरवरी को 'विश्व कैंसर दिवस' मनाया जाता है। दरअसल आज भी लगभग सभी लोगों के लिए कैंसर एक ऐसा शब्द है, जिसे अपने किसी परिजन के लिए डॉक्टर के मुंह से सुनते ही परिवार के तमाम सदस्यों की सांसें गले में अटक जाती हैं और पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसे में परिजनों को परिवार के उस अभिन्न अंग को सदा के लिए खो देने का डर सताने लगता है। बढ़ते प्रदूषण तथा पोषक खानपान के अभाव में यह बीमारी एक महामारी के रूप में तेजी से फैल रही है। भारत में तो कैंसर के करीब दो तिहाई मामलों का बहुत देर से पता चलता है और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हमारे देश में पिछले बीस वर्षों के दौरान कैंसर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है और कैंसर से मौतों का आंकड़ा साल-दर-साल निरंतर बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष कैंसर से पीड़ित लाखों मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं।

हालांकि कुछ वर्ष पूर्व तक कैंसर को लाइलाज रोग माना जाता था लेकिन कुछ वर्षों में कैंसर के उपचार की दिशा में क्रांतिकारी खोजें हुई हैं और अब अगर समय रहते कैंसर की पहचान कर ली जाए तो उसका उपचार किया जाना काफी हद तक संभव हो जाता है। कैंसर के संबंध में यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है किन्तु अगर इसका सही समय पर पता लग जाए तो लाइलाज मानी जाने वाली इस बीमारी का उपचार अब संभव है। यही वजह है कि देश में कैंसर के मामलों को कम करने के लिए कैंसर तथा उसके कारणों के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि वे इस बीमारी, इसके लक्षणों और इसके भयावह खतरे के प्रति जागरूक रहें।

कैंसर से लड़ने का सबसे बेहतर और मजबूत तरीका यही है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, जिसके चलते जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान हो सके और शुरूआती चरण में ही इसका इलाज संभव हो। यदि कैंसर का पता शीघ्र लगा लिया जाए तो उसके उपचार पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि जागरूकता के जरिये इस बीमारी को शुरूआती दौर में ही पहचान लेना बेहद जरूरी माना गया है क्योंकि ऐसे मरीजों के इलाज के बाद उनके स्वस्थ एवं सामान्य जीवन जीने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। हालांकि देश में कैंसर के इलाज की तमाम सुविधाओं के बावजूद अगर हम इस बीमारी पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे इस बीमारी का इलाज महंगा होना सबसे बड़ी समस्या है। वैसे देश में जांच सुविधाओं का अभाव भी कैंसर के इलाज में एक बड़ी बाधा है, जो बहुत से मामलों में इस बीमारी के देर से पता चलने का एक अहम कारण होता है।

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि 'कैंसर' आखिर है क्या? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है तो शरीर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमला करना शुरू कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई बार शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अपने आप तेजी से विकसित और विभाजित होने लगती हैं। कोशिकाओं के समूह की इस अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता हैं। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है और कैंसर की यह स्थिति बहुत घातक हो जाती है। दुनिया भर में कैंसर से लड़ने और इसे हराने के लिए निरन्तर चिकित्सीय खोजें हो रही हैं और इन प्रयासों के चलते ही अब कैंसर का शुरूआती चरणों में तो सफल इलाज संभव भी है। अगर शरीर में कैंसर होने के कारणों की बात की जाए तो हालांकि इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं लेकिन अक्सर जो प्रमुख कारण माने जाते रहे हैं, उनमें मोटापा, शारीरिक सक्रियता का अभाव, व्यायाम न करना, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल व नशीले पदार्थों का सेवन, पौष्टिक आहार की कमी इत्यादि इन कारणों में शामिल हो सकते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कैंसर के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते किन्तु किसी अन्य बीमारी के इलाज के दौरान कोई जांच कराते वक्त अचानक पता चलता है कि मरीज को कैंसर है लेकिन फिर भी कई ऐसे लक्षण हैं, जिनके जरिये अधिकांश व्यक्ति कैंसर की शुरूआती स्टेज में ही पहचान कर सकते हैं।

कैंसर के लक्षणों में कुछ प्रमुख हैं, वजन घटते जाना, रक्त की कमी होना, निरन्तर बुखार बने रहना, शारीरिक थकान व कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी होना, दौरे पड़ना शुरू होना, आवाज में बदलाव आना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी के दौरान खून आना, लंबे समय तक कफ रहना और कफ के साथ म्यूकस आना, कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, पेशाब और शौच के समय खून आना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन होना, माहवारी के दौरान अधिक स्राव होना इत्यादि। कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी, बायोलॉजिकल थैरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इत्यादि के जरिये कैंसर का इलाज होता है किन्तु यह प्रायः इतना महंगा होता है कि एक गरीब व्यक्ति इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए जरूरत इस बात की महसूस की जाती रही है कि कैंसर के सभी मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो या निजी अस्पतालों में, सरकार ऐसे मरीजों के इलाज में यथासंभव आर्थिक सहयोग करे क्योंकि जिस तेजी से देश में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए केवल सरकारी अस्पतालों के भरोसे कैंसर मरीजों के इलाज की कल्पना बेमानी ही होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कैंसर को लेकर समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं जाएं।

चिंतन मनन

प्रधानता आत्मा को

मनुष्य सामान्यतः जो बाह्य में देखता, सुनता, समझता है वह यथार्थ ज्ञान नहीं होता। किन्तु भ्रमवश उसी को यथार्थ ज्ञान मान लेता है। अवास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान समझकर और उसके अनुसार अपने कार्य करने केकारण मनुष्य अपने मूल उद्देश्य सुख-शान्ति की दिशा में अग्रसर न होकर विपरीत दिशा में चल पड़ता है। यथार्थ ज्ञान की अनुभावक मनुष्य की अंतरात्मा ही है। शुद्ध, बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उसको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्यापसकता। परमात्मा का अंश होने से वह उसी तरह सत्, चित् एवं आनंद है, जिस प्रकार परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति संभव नहीं है उसी प्रकार उसके अंश आत्मा में भी असत्य का प्रवेश सम्भव नहीं। मनुष्य की अंतरात्मा जो कुछ देखती, सुनती और समझती है, वही सत्य और यथार्थ ज्ञान है। अंतरात्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक-संतापों का स्वत- समाधान हो जाता है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है, किन्तु उसकी वाणी सूक्ष्मातिसूक्ष्म होती है, जिसे बाह्य एवं स्थूल श्रवणों से नहीं सुना जा सकता। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है किन्तु मौन विचार स्फुरण की भाषा में, जिसे मनुष्य अपनी कोलाहलपूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता। अन्तरात्मा की वाणी सुनने के लिए जरूरी है मनुष्य का मानसिक कोलाहल बन्द हो। अन्तरात्मा का सान्निध्य मनुष्य को उसकी आवाज सुनने योग्य बना देता है। यों मनुष्य की अन्तरात्मा उसमें ओतप्रोत है, पर उसका सच्चा सान्निध्य पाने के लिए उसे जानना आवश्यक है। परिचयहीन निकटता भी एक दूरी होती है। रेलयात्रा में कन्धे से कन्धा मिलाये बैठे दो आदमी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक-दूसरे से दूर होते हैं। अजनबी छोड़िए, जिन्दगी भर एक दूसरे केसाथ रहने पर भी आन्तरिक परिचय के अभाव में कई लोग एक-दूसरे से दूर ही रहते हैं। अन्तरात्मा जानने का एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु तथा सचेत रहा जाए। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है, वह उसकेविषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही उसे पा लेता है। आत्मा के विषय में अधिक से अधिकजिज्ञासु एवं सचेत रहिए। अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, सच्चा मार्ग निर्देशन पाएंगे, तो अज्ञान से मुक्त हों यथार्थ सुख-शान्ति के अधिकारी बनेंगे।

विचार मंथन

केंद्र सरकार की कटौती का बजट गंभीर आर्थिक चुनौती

(लेखक-सनत कुमार जैन/ईएमएस)

केंद्र सरकार के वर्ष 2025-26 के बजट के प्रावधान से साफ़ संकेत मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था गंभीर दबाव में है। बजट में घोषित बड़ी योजनाओं और आँकड़ों के पीछे जो सच्चाई छिपी है, उसमें खर्च में कटौती, कम आय सरकार की लिए गंभीर चुनौती है। सरकार ने जिन क्षेत्रों को विकास का इंजन बताया था, उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक धनराशि आवंटन में कटौती की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट, शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना सरकार के लिए गंभीर चुनौती है। सबसे पहले केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्ति पर नज़र डालें, तो बजट अनुमान के मुकाबले लगभग 78 हज़ार करोड़ रुपये का कम राजस्व सरकार के खजाने में आया है। यह आर्थिक मंदी का सीधा संकेत है। नेट टैक्स कलेक्शन भी अनुमान से करीब 1.62 लाख करोड़ रुपये कम प्राप्त हुआ है। जो बताता है, देश में उपभोग नहीं बढ़ रहा है। सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी की थी, उसके बाद भी बाजार में मांग नहीं बढ़ी है। ना ही पिछले महीने में व्यापारिक गतिविधियों में कोई सुधार हुआ है। सरकार ने कुल मिलाकर बजट में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के खर्च में कटौती की है। हैरानी की बात यह है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रोज़गार और बुनियादी ढांचे का मूल आधार माना जाता है, उसमें भी लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये की कटौती बजट में की गई है। यह सरकार के उस दावे के विपरीत है, जिसमें सरकार विकासोन्मुख बजट का दावा करती है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 3,686 करोड़ रुपये घटाए हैं। यह ऐसे समय में कटौती की गई है, जब देश में दूषित पानी, कुपोषण और महामारी के बाद की चुनौतियों से जूझ रहा है। इंदौर में दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत दूषित पानी पीने के कारण हुई है।

शिक्षा बजट में भी सरकार ने 6,700 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती की है। युवाओं और मानव संसाधन विकास के लिए यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। इसी तरह कृषि क्षेत्र पर देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है। उसमें भी करीब 7,000 करोड़ रुपये बजट में कम कर दिए हैं। इस बजट में सबसे ज्यादा चोट ग्रामीण विकास पर पड़ी है। जहाँ 53,000 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,200 करोड़ रुपये कम आवंटन किया गया है, जिससे गरीबों के घर का सपना और भी दूर हो गया है। जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं में बजट आवंटन का महज़ 2 प्रतिशत ही केंद्र सरकार ने खर्च किया है। जबकि दूषित पानी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए ज्यादा राशि के आवंटन की जरूरत थी। सबसे चिंताजनक स्थिति एससी, एसटी और ओबीसी कल्याण योजनाओं की गई कटौती है। अनुसूचित जाति की अभ्युदय योजना में 890 करोड़ की कटौती की गई है। ओबीसी छात्रवृत्ति में 690 करोड़, दलित पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप में 360 करोड़ आदिवासी विकास कार्यक्रम में 1,600 करोड़ से अधिक की कटौती की गई है। जो इस बात का स्पष्ट संदेश है, बजट कटौती के सहारे सरकार अपनी आय और खर्च के बीच के अंतर को सँभालने का प्रयास कर रही है। वर्तमान बजट में अर्थव्यवस्था में ठहराव देखने को मिल रहा है। प्रतिवर्ष टैक्स में जो वृद्धि हो रही थी, उसमें अब ठहराव आ गया है। अर्थव्यवस्था को बेहतर बताने के लिए सरकार ने 4.4 प्रतिशत का फिजिकल डेफिसिट बजट में रखा है। जो अर्थव्यवस्था के लिए संतोषजनक माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्र के बजट को कम किया गया है, उसे सरकार की उपलब्धि तो नहीं माना जा सकता है। वर्ष 2026-27 के बजट से रोज़गार की समस्या के निदान का कोई हल निकलेगा, यह बजट में दिख नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये और विदेशी निवेशकों का बाहर निकलने की चिंता इस बजट में दिख रही है। यह बजट वर्तमान की अर्थव्यवस्था में ज़मीनी सच्चाइयों के अनुसार नहीं है, यह कहा जा सकता है। सरकार ने आलोचनाओं से बचने और सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर बताने के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, वह वास्तविकता से दूर है। बजट किसानों, छात्रों, अल्पसंख्यक वर्ग की समस्या, वर्तमान की तुलना में और भी बढ़ेगी। इस बजट से यह संदेश मिल रहा है। सरकारी खजाने की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर कर्ज और ब्याज का बोझ है। पिछले दो दशक से केंद्र एवं राज्य सरकारों की आय में हर वर्ष जो वृद्धि हो रही थी उसमें अब ठहराव आने लगा है । कर्ज और ब्याज का बोझ केंद्र एवं राज्य सरकारों के ऊपर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। बजट का 25 से 40 फ़ीसदी कर्ज और ब्याज की अदायगी पर पहुंच गया है। जिसके कारण आगे चलकर केंद्र एवं राज्य सरकारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के 2026-27 के बजट में स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और होंडा मोटरसाइकिल के बीच रणनीतिक साझेदारी

मुंबई/इंदौर। देश के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने टू-व्हीलर फाइनेंसिंग के लिए एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य तकनीक-आधारित समाधानों के जरिए ग्राहकों को किफायती और सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराना है। इस गठबंधन के तहत, एयू बैंक होंडा का पसंदीदा फाइनेंसर होगा। बैंक अपनी एसटीपी तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ग्राहकों को पेपरलेस प्रक्रिया, त्वरित ऋण स्वीकृति और रीयल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। यह पहल विशेष रूप से पहली बार वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल सहायता सुनिश्चित करेगी। साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए एयू बैंक के डिप्टी सीईओ उत्तम टिबरेवाल ने कहा कि यह सहयोग मोबिलिटी फाइनेंस के विस्तार में एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, होंडा के सेल्स एवं मार्केटिंग डायरेक्टर योगेश माथुर ने कहा कि इस कोलैबोरेशन से देशभर की डीलरशिप पर ग्राहकों को पारदर्शी और सुलभ क्रेडिट विकल्प मिलेंगे। यह गठजोड़ एयू बैंक के यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्यात को बढ़ावा

मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेंगे

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत वाशिंगटन ने भारतीय सामानों पर जवाबी शुल्क 25 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। यह कदम दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखेगा। आईसीईए के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि इस समझौते से भारत एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत की अमेरिका की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहरी भागीदारी की रणनीति का समर्थन करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 19 फीसदी बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, निर्यात में 37.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। इस वृद्धि से भारत की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में हिस्सेदारी मजबूत होगी और उद्योग में नई निवेश संभावनाएँ खुलेंगी।

होरीबा ने प्रिस्टीन डीपटेक का किया अधिग्रहण

अहमदाबाद । होरीबा ग्रुप की कंपनी होरीबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रिस्टीन डीपटेक प्राइवेट लिमिटेड के सौ प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। होरीबा लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें भारत में अपनी आरएंडडी फैसिलिटी स्थापित करने के लिए प्रिस्टीन डीपटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी कर बेहद खुशी हो रही है। यह रणनीतिक साझेदारी एडवांस्ड मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके जरिए हम इनोवेशन पर फोकस करेंगे और बाजार में अपनी आर एंड डी क्षमताओं को और सशक्त बनाएंगे। यह साझेदारी भारतीय बाजार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है और ऐसी सॉल्यूशंस देने पर केंद्रित है, जो तकनीकी प्रगति और समाज में सार्थक योगदान दे।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद अडानी समूह के शेयरों में जबरदस्त उछाल

मुंबई।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। सबसे ज्यादा तेजी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के शेयर में रही, जो करीब 10 प्रतिशत के अपर सर्किट के पास ट्रेड करता है। शेयर बाजार में तेजी के माहौल के बीच अदाणी और अदाणी एनर्जी के शेयरों में भी 7 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है। इसके अलावा, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर, अंबुजा सीमेंट्स और अदाणी टोटल के शेयर भी 4 प्रतिशत से ज्यादा चढे है। अदाणी ग्रुप की कंपनियों में निवेशकों का भरोसा भारत-अमेरिका ट्रेड डील की वजह से और मजबूत हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने अदाणी ग्रुप को डील से फायदा उठाने वाले बड़े समूहों में शामिल बताया है।

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों का अमेरिका से सीधा कारोबार जुड़ा हुआ है, इसी वजह से उन्हें इस ट्रेड डील का बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, सोलर मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल कंपनियां और टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझौते से लाभ मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने मेड इन इंडिया उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जाहिर की है। इस भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया है।

इस बीच जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अदाणी समूह की तीन कंपनियों-अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड (एपीएसईजेड), अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल)-की रेटिंग शुरू की है। इन तीनों कंपनियों को स्टेबल आउटलुक के साथ लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा क्रेडिट रेटिंग दी गई है। जापान की रेटिंग एजेंसी ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) को ए- (स्टेबल) रेटिंग दी है।

रुपया बढ़त पर बंद

नई दिल्ली । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 30 पैसे की बढ़त के साथ ही 90.49 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपये में तेजी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अहम फैसले के बाद रुपया अचानक मजबूत स्थिति में आ गया। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। इस फैसले की खबर सामने आते ही शेयर बाजार और फॉरेक्स मार्केट में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। मंगलवार को इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.30 पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 91.49 पर बंद हुआ था। यानी शुरुआती कारोबार में ही रुपये ने 119 पैसे की बड़ी छलांग लगा दी। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक, यह पिछले चार वर्षों में एक दिन की सबसे बड़ी मजबूती है। इससे पहले कोरोना काल के दौरान इस तरह की तेजी देखी गई थी। बाजार के जानकारों ने कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता बाजार के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 9 महीने की देरी के बाद टैरिफ घटाने की घोषणा की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी समर्थन मिला। 18 फीसदी टैरिफ भारत के लिए पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति बनाता है, जिससे निर्यातकों को फायदा होगा।

कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया कोटक सर्विसेज फंड, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पर फोकस

मुंबई/इंदौर ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ सर्विस सेक्टर में निवेश के अवसरों को भुनाने के लिए कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने 'कोटक सर्विसेज फंड' लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो विशेष रूप से सेवा क्षेत्र की कंपनियों पर केंद्रित होगी। यह नया फंड ऑफर (एनएफओ) 4 फरवरी 2026 को खुलेगा और 18 फरवरी 2026 को बंद होगा। निवेशक न्यूनतम 1,000 रुपये के साथ इस स्कीम में भागीदारी कर सकते हैं। भारत की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग 55त्न का योगदान देने वाला सर्विस सेक्टर निवेश के लिहाज से बेहद आकर्षक है। कोटक सर्विसेज फंड का उद्देश्य टेलीकॉम, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की क्षमता का लाभ उठाना है। फंड प्रबंधन के लिए 'बीएएमवी' (बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और वैल्यू) फ्रेमवर्क का पालन किया जाएगा, जो उचित कीमत पर बेहतर ग्रोथ वाले स्टॉक्स चुनने में मदद करेगा। लॉन्च के अवसर पर कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी निलेश शाह ने कहा, बढ़ती आय और डिजिटलीकरण के कारण भारत की सर्विस इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आ रहा है। यह फंड निवेशकों को इस बदलाव का हिस्सा बनने और लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। वहीं, फंड मैनेजर रोहित टंडन ने बताया कि पोर्टफोलियो में उन कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अपने मुनाफे को बरकरार रखने और बिजनेस मॉडल को स्केल करने में सक्षम हैं। यह फंड लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप की अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों का एक संतुलित मिश्रण होगा।

ट्रेड डील के बाद झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 2,072 अंक ऊपर आया

निफ्टी 25,727 पर पहुंचा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी उछाल के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के कारण आई है। इससे निवेशकों में उत्साह रहा और जमकर खरीददारी हुई। वहीं दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों से भी घरेलू बाजार को बल मिला। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 2,072.67 अंक ऊपर आकर 83,739.13 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 639.15 अंक बढ़कर 25,727.55 पर बंद हुआ। आज रियल्टी और वित्तीय शेयरों के ऊपर आने से भी बाजार उछाल। मुख्य सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी 4.79 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 3.27 फीसदी) की तेजी के साथ सबसे अधिक लाभ में रहे जबकि निफ्टी हेल्थकेयर 3.16 फीसदी, निफ्टी इन्फ्रा 3.03 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में 30 में से 28 शेयर लाभ के साथ ही उछले। इसके अलावा अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, पावर ग्रिड, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एलएंडटी, एक्सिस बैंक, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, के शेयर भी ऊपर आये। दूसरी ओर बीईएल और टेक महिंद्रा के शेयरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। आज लार्जकैप के अलावा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,639.50 अंक या 2.84 फीसदी की तेजी के साथ 59,307.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 465.60 अंक की तेजी के साथ 16,988.95 पर था।बाजार जानकारों के अनुसार भारत-अमेरिका ट्रेड डील से भी बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। इससे भारत को तेज विकास दर हासिल करने में सहायता मिलेगी। इससे पहले आज सुबह बाजार की तेजी के साथ शुरुआत हुई। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील की आधिकारिक घोषणा होते ही निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और बाजार में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सुबह । सेंसेक्स

शानदार बढ़त के साथ 85,323 अंक पर खुला। सुबह सेंसेक्स 2,492.06 अंक की उछाल के साथ 84,158.52 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी-50 भी दमदार तेजी के साथ 26,308 अंक पर खुला। सुबह यह 760.70 अंक की बढ़त के साथ 25,849.10 अंक पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं वैश्विक स्तर पर एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। चीन का सीएसआई 300 इंडेक्स 0.51 फीसदी चढ़ा, हांगकांग का हैंग सेंग 0.78 फीसदी ऊपर रहा, जापान का निक्केई 3.09 फीसदी और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.3 फीसदी बढ़ा। अमेरिकी बाजारों में वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 में 0.54 फीसदी , नैस्डैक में 0.56 फीसदी और डाउ जोंस में 1.05 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

मस्क की कंपनी ने एआई स्टार्टअप एक्सएआई का अधिग्रहण किया

वाशिंगटन।

दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क ने घोषणा की है कि उनकी एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने उनके एआई स्टार्टअप एक्सएआई का अधिग्रहण किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाना है। कारोबारी मस्क के अनुसार, बड़े पैमाने पर सैटेलाइट लांच कर अंतरिक्ष में डेटा सेंटर जैसी संरचना बनाई जाएगी। हर साल 10 लाख टन सैटेलाइट लांच करने पर करीब 100 गीगावाट एआई कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में यह क्षमता धरती से 1 टेरावॉट तक पहुंच सकती है। मस्क ने बताया कि एआई संचालन के लिए अत्यधिक बिजली की आवश्यकता होती है और लंबे समय में इसका सबसे प्रभावी समाधान स्पेस-बेस्ड एआई है। अंतरिक्ष में सूरज की लगातार रोशनी मिलने के कारण, धरती पर बनाए गए डेटा सेंटर की तुलना में बहुत कम लागत में कंप्यूटिंग पॉवर उपलब्ध हो सकती है। इससे कंपनियां अपने एआई मॉडल को तेज़ और बड़े स्तर पर ट्रेन कर पाएंगी और डेटा प्रोसेसिंग भी अधिक कुशल होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि धरती पर बढ़ती बिजली और कूलिंग की जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है और इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट 2026 में नई वी3 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लांच करेगा, जो मौजूदा सैटेलाइट्स से 20 गुना अधिक क्षमता वाली होंगी। भविष्य में हर घंटे 200 टन वजन लेकर उड़ान भरने की योजना है, जिससे लाखों टन सामान अंतरिक्ष में

पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही, अगली पीढ़ी के डायरेक्ट-टू-मोबाइल सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, जो धरती के हर कोने में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराएंगे। मस्क का कहना है कि अंतरिक्ष में एआई और ऊर्जा का उपयोग हमारी सभ्यता की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का सबसे स्थायी और प्रभावी तरीका है। इस योजना से एआई की तरक्की तेज होगी और ऊर्जा की खपत कम होगी।

विदेश से घर लौटते समय बढ़ी ड्यूटी-फ्री सीमा

मुंबई । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बैगेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं, जो 2 फरवरी से प्रभावी हुए। नए नियमों के तहत भारतीय निवासी या वैध वीजा वाले विदेशी नागरिक अब 75,000 रुपये तक का सामान बिना ड्यूटी चुकाए ला सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। विदेशी पर्यटकों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये कर दी गई है। एक साल से अधिक विदेश में रहने वाले भारतीय यात्रियों के लिए गहनों की सीमा बढ़ा दी गई है। महिलाएं 40 ग्राम और पुरुष 20 ग्राम तक सोने के आभूषण बिना ड्यूटी ला सकते हैं, बशर्ते यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो। 18 साल से ऊपर के यात्री एक नया लैपटॉप या नोटपैड पूरी तरह ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं। सिगरेट, शराब की अतिरिक्त मात्रा, सोने-चांदी की छड़ें और टीवी जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान इस छूट के बाहर हैं। विदेशी मुद्रा के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

भारतीय राजनीति को झकझोर देने वाली रक्षा कंपनी की सहयोगी से अडानी समूह ने किया समझौता

नई दिल्ली।

इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड क्लीन चिट मिलने के पांच साल बाद फिर भारत के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश को तैयार है। यह वही बहुचर्चित कंपनी हैं जिसका नाम वीवीआईपी हेलिकॉप्टर कांड से जुड़ा था। इस कांड ने करीब एक दशक तक भारतीय राजनीति को झकझोर दिया था। अगस्ता की पैतृक कंपनी लियोनार्डो के साथ अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दे दिया है। अडाणी ग्रुप के अनुसार इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को होगी। लियोनार्डो कभी फिनमैकेनिका के नाम से जानी जाती थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3,600 करोड़ का एक वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद घोटाला है। इसमें कंपनी पर 12 एडब्ल्यू-101 (एडब्ल्यू-101) हेलिकॉप्टर की खरीद में वायुसेना के अधिकारियों और बिचौलियों को करीब 360 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। भारत ने 2014 में सौदे को औपचारिक रूप से रद्द करने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। सबूतों के अभाव में पहले इटली की अदालत ने और बाद में नवंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता वेस्टलैंड को क्लीन चिट दे दी थी।

दरअसल यह सौदा 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान इटली की कंपनी फिनमैकेनिका की सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हुआ था। 2013 में इटली की जांच एजेंसियों ने रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच शुरू की। इस सौदे में बिचौलियों की भूमिका सामने आई। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और नौबत इतना आ गई कि सौदे के समय वायु सेना प्रमुख रहे एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी और कुछ अन्य लोगों को जेल जाना पड़ा।

सीबीआई ने 2010 में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (करीब 2,666 करोड़ रु.) के नुकसान का आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2016 में दायर अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (करीब 225 करोड़ रु.) मिले थे। इधर, सीबीआई का केस चलता रहा। रक्षा मंत्रालय ने इस केस से जुड़ी भारतीय कंपनी डेफसिस प्राइवेट लिमिटेड पर पिछले साल जून में प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के आदेश को निरस्त कर दिया।

बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना का उत्पादन लक्ष्य बढ़ा

- वित्त वर्ष 27 में बल्क ड्रग्स के लिए 500 टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य

नई दिल्ली ।

वित्त वर्ष 27 में फार्मास्युटिकल्स विभाग ने बल्क ड्रग्स, मेडिकल उपकरण और अन्य फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस साल बजट आवंटन में 2.24 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए तीन योजनाओं के लिए कुल 2,499.84 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि वित्त वर्ष 26 में यह 2,444.93 करोड़ रुपए था। विभाग वित्त वर्ष 27 में बल्क ड्रग्स के लिए 500 टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रख रहा है।

इससे इस साल कुल 1,250 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स का उत्पादन होने का अनुमान है। इस पहल का उद्देश्य जरूरी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (एपीआई) का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और उन दवाओं पर निर्भरता कम करना है, जिनके कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं हैं। सरकार ने हाल ही में चीनी उत्पादकों द्वारा दामों में कमी और डंपिंग को रोकने के लिए पेनिसिलिन-जी, एमोक्सिसिलिन और 6-एपीए जैसी एपीआई के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) तय किया है। बल्क ड्रग्स योजना के बाहर आने वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए वित्त वर्ष 27 में 1.08 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है, जो वित्त वर्ष 26 के 90,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से बढ़कर है। योजना के तहत बायोफार्मास्युटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंटेड और पेटेंट समाप्ति के करीब दवाएं, ऑटो-इम्यून दवाएं और कैंसर रोधी दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मकसद उच्च मूल्य वाली दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत को फार्मास्युटिकल आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत करना है।

कैंसर और दुर्लभ बीमारी की दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने से मरीजों को राहत

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने कैंसर की 17 महंगी दवाओं और सात दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर 5-10 फीसदी आयात शुल्क तुरंत हटाने का निर्णय लिया है। इसका मकसद मरीजों के लिए इन उपचारों को सुलभ बनाना और लागत को कम करना है। इस कदम से वैश्विक और घरेलू दवा कंपनियों को भी फायदा होगा, जिनके पोर्टफोलियो में आयातित दवाएं शामिल हैं। इस छूट से नोवार्टिस, इलाई लिली, एस्ट्राजेनेका, रोश जैसी कंपनियां लाभान्वित होंगी। उदाहरण के लिए, नोवार्टिस का रिबोसिस्लिब और इलाई लिली का एबेमासिस्लिब ब्रेस्ट कैंसर में उपयोग होता है। एस्ट्राजेनेका का ट्रेमेलिमुमैब लिवर कैंसर और रोश की वेनेटोक्लाक्स क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के इलाज में प्रयोग होती हैं। इसके अलावा, ऐबवी, ब्लूप्रिंट मेडिसिन्स, बेयर और ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब जैसी कंपनियों की आयातित इम्यूनोथेरेपी भी लाभ में रहेंगी। एल्नीलम फार्मास्युटिकल्स को प्राइमरी हाइपरोक्सालुरिया टाइप 1 के लिए लुमासिरेन पर छूट मिलेगी। इसके अलावा, हेरेडिटरी एंजियोएडेमा और प्राइमरी इम्यूनोडिफिशिएंसी डिसऑर्डर (पीआईडीडी) के इलाज में दवा आपूर्तिकर्ताओं को स्थिर मांग और बेहतर किफायत मिलेगी। मरीजों के लिए इसका सीधा फायदा यह होगा कि महंगी दवाओं की लागत में थोड़ी कमी आएगी। लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की दवाओं जैसे रिबोसिस्लिब और एबेमासिस्लिब की कीमतें कम होने से इलाज जारी रखना आसान होगा। ट्रेमेलिमुमैब जैसी इम्यूनोथेरेपी भी अधिक सुलभ हो जाएगी।

टैक्स विवाद निपटाने की रफ्तार तेज, 2 लाख से ज्यादा अपील सुलझाने का लक्ष्य

नई दिल्ली ।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख से अधिक सीआईटी (ए) मामलों का निपटान करने का लक्ष्य रखा है। 20 जनवरी तक 1.65 लाख मामले निपटाए जा चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष 1.72 लाख मामलों का निपटान हुआ था। वर्तमान में लगभग 5.4 लाख अपील मामले लंबित हैं, जिनमें विवादित कर राशि 16.75 लाख करोड़ रुपये है। अब मूल्यांकन और जुर्माने की कार्रवाई एक ही आदेश में की जाएगी, जिससे अलग मुकदमेबाजी समाप्त होगी। यदि करदाता अंडर-रिपोर्टिंग स्वीकार करते हैं और भुगतान करते हैं, तो जुर्माने में 50 फीसदी की छूट और गलत रिपोर्टिंग पर जुर्माना 200 फीसदी से घटाकर 100 फीसदी किया जाएगा। विभाग ने अपडेटेड रिटर्न सुविधा शुरू की है, जिससे करदाता चार साल तक की विसंगतियों को स्वेच्छा से सुधार सकते हैं। अब तक 1.22 करोड़ अपडेटेड रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इस सुविधा से कर अनुपालन और कर संग्रह में पारदर्शिता बढ़ी है। आईटी, आईटीईं सेवाएं, सॉफ्टवेयर विकास और केपीओ क्षेत्रों के लिए 15.5 फीसदी एकीकृत सेफ हार्बर मार्जिन लागू किया गया है। 2,000 करोड़ रुपये की पात्रता सीमा के कारण अधिकांश कंपनियां इसका लाभ ले सकेंगी। 44,000 कंपनियों में से लगभग 30 फीसदी आईटी/आईटीईं क्षेत्र से संबंधित हैं। केवल 90 कंपनियां बाहर हैं, जिनमें से 60 के पास एपीए है और शेष 30 भविष्य में एपीए ले सकती हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अंडर-19 विश्व कप सेमीफाइनल में आज अफगानिस्तान पर जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

हरारे (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम का बुधवार को यहां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। अब तक इस टूर्नामेंट में सभी मैच जीतने वाली भारतीय टीम इस मैच में भी जीत की प्रबल दावेदार रहेगी। भारतीय टीम ने अब तक पांच बार 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 में ये खिताब जीता है। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में भी जीत दर्ज कर छठे खिताब की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी।

भारतीय टीम ने इससे पहले के मुकाबल में पाकिस्तान को हराया था जिससे उसके हौंसले बुलंद हैं। भारतीय टीम ने अब तक अपने सभी पांच मैच आसानी से जीते हैं, जिसमें सुपर सिक्स चरण में पाकिस्तान के खिलाफ मिली 58 रनों की जीत भी शामिल है। भारतीय टीम इसके बाद भी इस मैच को हल्के में नहीं लेगी। इसका कारा है कि अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उसने अपने पांच मैचों में से चार जीते हैं। उसे एक ही मैच में श्रीलंका ने हराया था। उसके खिलाड़ियों ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है।

भारतीय टीम के बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने अब तक इस टूर्नामेंट में जमकर रन बनाये हैं। ये दोनो ही ये सिलसिल बनाये रखना चाहेंगे। कुंडू ने अब तक पांच मैचों में दो अर्धशतकों की मदद से 199 रन बनाए हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 196 रन बनाये हैं। इस दौरान उन्होंने पांच अर्धशतक लगाये हैं। ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा ने अब तक ?(पांच मैचों में 172 रन बनाये हैं जिसमें ग्रुप चरण में जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया शतक 109 रन भी शामिल हैं।

कप्तान आयुष म्हात्रे और आरोन जॉर्ज को अत तक अधिक रन नहीं बना पाये हैं और टीम को इनसे इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की

उम्मीद रहेगी। आयुष ने पांच मैचों में केवल 99 रन बनाए हैं। सलामी बल्लेबाज आरोन ने तीन पारियों में केवल 46 रन बनाये हैं।

आयुष ने हालांकि गेंदबाज़ी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने पांच मैचों में छह विकेट लिए हैं। टीम की गेंदबाजी की कमान तेज गेंदबाज हेनिल पटेल और आरएस अंबरीश के पास रहेगहै। इसके अलावा स्पिन की जिम्मेदारी खिलन पटेल के पास रहेगी। पटेन ने पांच मैचों में आठ विकेट लिए हैं। दूसरी ओर महबूब खान की कप्तानी में अफगान टीम भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेगी।

टीम इस प्रकार है

भारत अंडर-19: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन सिंह।

अफगानिस्तान अंडर-19: महबूब खान (कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, फैसल शिनोजादा, खालिद अहमदजई, उस्मान सादात, उजैरुल्लाह नियाजई, अब्दुल अजीज, अकील खान, खातिर स्टानिकजई, नाजीफुल्लाह अमीरी, नूरिस्तानी उमरजई, रूहुल्लाह अरब, सलाम खान, वहीदुल्लाह जादरान, जैतुल्लाह शाहीन।

जगदीशन की आक्रामक बल्लेबाजी से भारत ए ने अभ्यास मैच में अमेरिका को हराया

नवी मुम्बई (एजेंसी)। नारायण जगदीशन की आक्रामक बल्लेबाजी से भारत ए ने यहां टी20 विश्वकप क्रिकेट के पहले ही अभ्यास मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को 38 रनों हरा दिया। इस मैच से बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी टीम में अच्छी वापसी की है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज जगदीशन ने केवल 55 मैचों में ही 104 रन बना दिये। अपनी इस पारी मे जगदीशन ने 11 चौके और 5 छक्के लगाये और अमेरिकी टीम को कोई अवसर नहीं दिया। इस मैच में अमेरिकी कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारत ए ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन बनाए थे। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिकी टीम 19.4 ओवर में ही 200 रनों पर ही आउट हो गयी। उसकी ओर से इस मैच में अमेरिकी टीम की ओर से भारतीय मूल के बल्लेबाज संजय कृष्णमूर्ति ने 18 गेंदों में 41 रन बनाये। भारतीय टीम की ओर से कप्तान आयुष बदोनी ने नाबाद 60 रन 26 गेंद पर बनाए। तिलक वर्मा ने भी वापसी की और 38 रन बनाए। प्रियांश आर्या ने पारी की शुरुआत करते हुए तेजी से 13 गेंद पर 28 रन बनाये। भारतीय टीम की ओर से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। इस मैच में वापसी करते हुए तिलक ने अच्छी बल्लेबाजी की। तिलक ने स्पिनरों हरमीत सिंह और नोस्तुश केनजीगे के खिलाफ दो जोरदार छक्के लगाये। तिलक ने इसके बाद गेंदबाजी करते हुए एक विकेट लिया और एक और कैच भी पकड़ा।

टी20 विश्कवप में सलामी बल्लेबाज पर फैसला 7 फरवरी को होगा : सूर्यकुमार

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि टी20 विश्वकप में अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय टीम की पारी की शुरुआत कौन करेगा। इसका फैसला सात फरवरी को अमेरिक के खिलाफ होने वाले पहले मैच में हो जाएगा। भारतीय टीम में इसके लिए संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे दावेदार है पर जिस प्रकार से सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में असफल रहे हैं। उससे तय है कि अभिषेक के साथ पारी शुरु करने की जिम्मेदारी ईशान को ही मिलेगी। सैमसन जहां सीरीज के पांच मैचों में केवल 46 रन बना पाये। वहीं ईशान ने एक शतक और अर्धशतक सहित करीब 250 रन बनाये थे। ऐसे में सैमसन का दावा काफी कमजोर हो गया है। वहीं सूर्यकुमार ने कहा कि पारी की शुरुआत कौन करेग। अभी इसपर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि ईशान और सैमसन दोनों ही अंतिम ग्यारह के दावेदार हैं। टीम प्रबंधन सभी पक्षों पर ध्यान देने के बाद अंतिम फैसला करेगा।

कप्तान ने का कि बल्लेबाज तिलक वर्मा भी फिट हो गये हैं और वह मध्यक्रम में अपनी जगह पर वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि तिलक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और वापसी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में दल के सभी 15 खिलाड़ी अंतिम एकादश में जगह पाने के दावेदार हैं, जिससे चयन और भी कठिन हो गया है। सूर्यकुमार ने टीम अपनी आक्रमक रणनीति पर चलेगी। इसलिए शीर्ष क्रम को आक्रामक होकर ही खेलना होगा। उन्होंने संकेत दिए कि टीम को नंबर 7 या 8 तक एक अतिरिक्त विशेषज्ञ बल्लेबाज की जरूरत हो सकती है। साथ ही कहा कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल पर रहेगी।

वहीं हार्दिक पांड्या के अलावा शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा को भी गेंदबाजी दी जा सकती हैं। ऐसे में टीम सात बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स के साथ एक मजबूत संयोजन बनाएगी। कप्तान ने कहा कि घरेलू हालातों में खेलने पर दबाव आता है पर खेल में ये चलता रहता है। उनका प्रयास टीम की खिताब बरकरार रखने में सहायता करना रहेगा। उन्होंने कहा कि अभिषेक , ईशान अपनी स्वाभाविक शैली में खेलते हैं और उन्होंने सभी को उसी अनुसार खेलने को कहा है।

कमिंस टी20 विश्वकप से बाहर हुए, ड्वार्शियस शामिल

मेलबर्न (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गये हैं। कमिंस ने पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण विश्वकप कप से नाम वापस ले लिया है। कमिंस ने कहा कि उनका लक्ष्य आगामी टेस्ट सत्र के लिए पूरी तरह से फिट होना है ताकि वह सभी मैच खेल सकें। इसलिए उन्होंने तय किया कि विश्वकप से बाहर रहना ही ठीक है। कमिंस के बाहर होने के कारण उनकी जगह पर बेन ड्वार्शियस को टीम में शामिल किया गया है। कमिंस ने कहा, मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं कुछ सप्ताह तक आराम करूंगा और फिर आगे की योजना बनाऊंगा।

उन्होंने कहा, एडिलेड टेस्ट मैच के

बाद हमें पता था कि चोट को पूरी तरह से ठीक होने में चार से आठ सप्ताह का समय लगेगा। शुरू में हमें लगा था कि इसमें चार सप्ताह ही लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था पर अभी किये एक स्कैन में चिकित्सकों ने पाया कि मुझे पूरी तरह ठीक होने में कुछ सप्ताह और लगेंगे।

ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैचों का कार्यक्रम अगस्त से शुरू होगा, तब उसे बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा। इसके बाद वह सितंबर में टेस्ट और एकदिवसीय के लिए टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। टीम इसके बाद न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी और फिर पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगा। इसके बाद वह अगले साल मार्च में मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने पर गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेलेगी। इसके बाद इंग्लैंड में एशेज सीरीज, एकदिवसीय विश्व कप और जून में लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा। कमिंस ने कहा, हमने सोचा कि आगामी सत्र में क्रिकेट मैचों की संख्या को देखते हुए साल के पहले छह महीने में संयम बरतना काफी अच्छा रहेगा। चोट ठीक हो जाएगी और इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं अभी इसको लेकर सतर्कता नहीं बरतता तो समस्या बढ़ सकती थी। कमिंस को उम्मीद है कि वह 26 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करने के लिए समय पर फिट हो जाएंगे।

आईसीसी पाकिस्तान बोर्ड पर प्रतिबंध लगाये : गावस्कर

मुम्बई । भारतय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप से ठीक पहले भारत के खिलाफ मैच खेलने से इंकार किया है । ऐसे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाना चाहिये । पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि टीम टी20 विश्व कप खेलेगी पर भारत के खिलाफ मैच में नहीं उतरेगी । उसने पाक बोर्ड (पीसीबी) से इस मैच का बहिष्कार करनके को कहा है । पाक के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है यहां तक कि उसके खिलाड़ी भी इससे सहमत नहीं हैं । गावस्कर भी इससे बेहद नाराज हैं । उन्होंने आईसीसी से अपील की है कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के लिए पीसीबी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये । भारत-पाक का मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है । इसके लिए पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत ही कोलंबो में खेलने का अवसर मिला पर अपनी अड़ियल रवैये और बांग्लादेश का साथ देने की जिद को लेकर पाक सरकार ने मैच खेलने से इंकार किया है । गावस्कर का मानना है कि आईसीसी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिये । जिससे अन्य टीम के सामने मिसाल पेश की जा सके ।

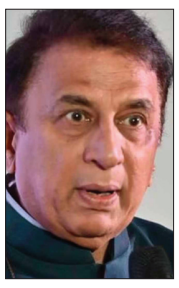

वेस्टइंडीज को विश्वकप में बेहतर गेंदबाजी करनी होगी : कोच सैमी

जमैका । वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश हैं । सैमी के अनुसार उनकी टीम को अगर टी20 विश्वकप जीतना है तो उसके गेंदबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा । सैमी के अनुसार उनकी टीम को हाल में दक्षिया अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज के अलावा अफगानिस्तान से भी हार का सामना करना पड़ा था । इससे साफ है कि खिलाड़ी फार्म में नहीं हैं और उन्हें काफी सुधार करने होंगे । उसके गेंदबाजों को विरोधी टीम के खिलाफ तीन मैचों में केवल 10 विकेट ही मिल पाये थे । पहले दो मैचों में ही टीम ने 401 से अधिक रन दे दिये थे । ऐसे में कोच का कहना है कि सब कुछ गेंदबाजों पर निर्भर करेगा । उनका प्रदर्शन से ही तय होगा कि टीम कहां तक पहुंचेगी । कोच कहा, उम्मीद है, हम ऐसा क्रिकेट खेल पाएंगे, जिससे हमें जीतने में सहायता मिले । जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है । मुझे पता है कि गेंदबाजी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी । हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में नई योजना के साथ उतरेंगे । सैमी साल 2012 और 2016 में वेस्टइंडीज की टीम ने विश्व कप जीता था, तो उस समय सैमी भी टीम में शामिल थे । उनका मानना है कि इस बार के विश्व कप के लिए बल्लेबाजी ईकाई अच्छी है पर गेंदबाजी में परेशानी हैं । सैमी ने कहा, मैं बल्लेबाजी के तरीके से खुश हूं । मैं चाहूंगा कि स्पिनर प्रभावी गेंदबाजी करें । दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हमार स्पिनर बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा पाये थे ।।

रायडू को भारतीय टीम के टी20 विश्वकप जीतने की उम्मीद

हैदराबाद । पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने भारतीय टी20 टीम की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इस बार भी वह खिताब जीत सकती है । भारतीय टीम ने पिछल बार वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुए विश्वकप को जीता था । जिससे वह इस बार भी बरकरार रखना चाहेगी । रायडू के अुनसार जिस प्रकार से भारतीय टीम अच्छे फार्म में है । उससे वह अपना विश्वकप खिताब बरकरार रखने में सक्षम नजर आती है । भारतयी टीम ने जिस प्रकार से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज में खेला है उससे रायडू बेहद प्रभावित हैं । भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज 4-1 से जीती है । रायडू ने कहा कि टीम का आत्मविश्वास, रुख और निडर क्रिकेट यह दिखाता है कि भारत आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है । रायडू ने कहा कि इस भारतीय टीम की सोच बाकी टीमों से अलग है । उनके अनुसार, खिलाड़ी बिना किसी दबाव के खेल रहे हैं और यही निडरता उन्हें आक्रामक बनाती है । इसलिए भारतीय टीम के पास वह सब है जो विश्वकप जीतने के लिए चाहिये । ऐसे में अगर टीम सही दिशा में रहीं, तो 2026 में भी भारतीय टीम ट्रॉफी जीत सकती है । भारतीय टीम को विश्वकप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से खेलना है । इसके बाद टीम इंडिया नई दिल्ली में नामीबिया, कोलंबो में पाकिस्तान और अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच खेलेगी ।

भारत-पाक मैच नहीं होने से दोनो ही बोर्ड को 200-200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान

मुम्बई (एजेंसी)। पाकिस्तान सरकार ने सात फरवरी से शुरु होने वाले आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला किया है। इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की मुश्किलें भी बढ़ गयी हैं क्योंकि भारत-पाक मैच के रोमांच के कारण सबसे अधिक राजस्व इसी मैच से मिलता है। एक रिपोर्ट के अुनसार इस मैच से तकरीबन 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4,500 करोड़ रुपये) की आय होने की संभावना थी। इसमें प्रसारण अधिकार, विज्ञापन, प्रायोजन राशि, टिकट बिक्री आदि से होने वाली आया शामिल है। दुनिया में किसी भी दूसरे क्रिकेट मैच से इतनी अधि कमाई नहीं होती है। ऐसे में इस मैच के नहीं होने पर में भारत और पाकिस्तान दोनों ही बोर्ड को करीब 200-200 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है। सकता है.

इसमें टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग से होने वाली आय भी शामिल है। गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान टी20 मैच के लिए

विज्ञापन दरें विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा होती हैं। ये 10 सेकंड के स्लॉट के लिए 25 से 40 लाख रुपये के बीच रहती हैं। इस मैच से केवल विज्ञापन से ही करीब 300 करोड़ रुपये की आय हो जाती है। वहीं अन्य विश्वकप मैचों की कीमत करीब 138 करोड़ रुपये होती है। इस प्रकार देखा जाये तो , भारत-पाकिस्तान मैच से होने वाली आय दोगुनी से अधिक है।

ऐसे में इस मैच के नहीं होने से प्रसारणकर्ताओं को विज्ञापन के अलावा अन्य स्रोतों से भी कम कमाई इोगी क्योंकि विश्वकप कप देखने वाले प्रशंसकों की संख्या भी घटेगी। इससे टूर्नामेंट के अन्य मैचों की कमाई भी घटना तय है। इस प्रकार प्रसारकों केा करीब 370 से 400 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है। ऐसे में आईसीसी के राजस्व में भी कमी आयेगी। इससे उसके सदस्य बोर्डों को मिलने वाली रकम भी कम हो जाएगी। ऐसे में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड पर भले ही अधिका प्रभाव न पड़े पर आईसीसी पर आधारित छोटे बोर्डों की मुश्कलें बढ़ जाएंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार मैच रद्द होने की स्थिति में भारत और पाकिस्तान दोनों को करीब 200-200 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। बीसीसीआई इससे झेल लेगा पर पाक बोर्ड का दिवाला निकलना तय नजर आता है।

पीसीबी को आईसीसी की कुल कमाई का करीब 5.75फीसदी हिस्सा मिलता है, जो सालाना लगभग 34.5 मिलियन डॉलर होता। अब पीसीबी के स्वयं हटने से उसे बीमा सुरक्षा नहीं मिली है जिससे पीसीबी पर कानूनी कार्रवाई होने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईसीसी प्रसारणकर्ताओं के नुकसान की भरपाई के लिए पीसीसी को दी जाने वाली राशि में बड़ कटौती कर सकती है।

पाकिस्तान के स्पिनर तारिक के एक्शन को भारतीय अंपायर ने सही बताया

मुम्बई (एजेंसी)। पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सवाल उठे हैं । तारिक के एक्शन को ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन ने गलत बताया है । वहीं भारतीय अंपायर अनिल चौधरी ने कहा है कि आईसीसी के नियमों के अनुसार तारिक का ऐक्शन ठीक है । उन्होंने कहा, अभी तारिक के ऐक्शन को लेकर एक वीडियो मेरे पास आया है, । इसमें उनका जो ऐक्शन है थोड़ा साइड वाला है और थोड़ा अलग है वह थोड़ा रुककर गेंद डालते हैं, क्योंकि वो सारी गेंद एक ही तरह से डालते हैं और उनका जो आर्म है, उसमें बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं है जो आईसीसी नियमों के अनुसार ठीक है । ऐसे में मेरे हिसाब से उनका ऐक्शन सही है । इस स्पिनर ने गत तीन महीने में केवल 3 ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेले हैं । हैरानी की बात ये है कि वे तीन सीरीजों में 3 मैच ही खेल पाये हैं । ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में दूसरे टी20 मैच में उन्होंने 2.4 ओवर गेंदबाजी की । जिसमें 16 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए । 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के करियर में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं । इस गेंदबाज का पाक टीम एक रहस्यमयी स्पिनर के तौर पर कभी-कभी ही उपयोग करती है ।

भारतीय निशानेबाजी के लिए बड़ी उपलब्धि ! अगले साल भारत में होगी एशियाई ओलंपिक क्वालीफाइंग चैंपियनशिप

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय निशानेबाजी प्रेमियों के लिए एक उत्साहजनक खबर है। भारत अगले साल एशियाई ओलंपिक क्वालीफाइंग निशानेबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह टूर्नामेंट न केवल एशियाई देशों के शीर्ष निशानेबाजों को एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि इसमें खिलाड़ियों के पास सीधे ओलंपिक कोटा हासिल करने का सुनहरा अवसर भी होगा। भारत को यह मेजबानी मिलना देश की विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है।

यह भारतीय निशानेबाजी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी क्योंकि वह पहले ही एक अन्य ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी हासिल कर चुका है। एशियाई प्रतियोगिता में ओलंपिक के लिए आठ स्थान अगले वर्ष 21 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में होने वाले विश्व कप (राइफल/पिस्टल/शॉटगन) में उपलब्ध 12 कोटा स्थानों के अतिरिक्त होंगे। एशियाई निशानेबाजी परिसंघ ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव को लिखे पत्र में इसकी पुष्टि की।

एनआरएआई ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में होगा और इसकी तिथियों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एशियाई निशानेबाजी परिसंघ (एएससी) ने पत्र में कहा, ''हम भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को एशियाई राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी हासिल करने पर बधाई देते हैं, जहां लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए आठ कोटा स्थान वितरित किए जाएंगे।'' पीटीआई के पास मौजूद पत्र में कहा गया है, ''हमें पूरा विश्वास है कि आपके (एनआरएआई) नेतृत्व में चैंपियनशिप का आयोजन उच्चतम मानकों के अनुरूप होगा और यह एक सफल प्रतियोगिता साबित होगी।''

देव को उम्मीद है कि इन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय निशानेबाज ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''हमारे खिलाड़ियों को दो ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा जो उन्हें अपनी धरती पर खेलने हैं और जिनमें वे अधिक से अधिक कोटा स्थान हासिल कर सकते हैं। मैं एएससी के महासचिव इंजीनियर अल ओतैबी और उनकी टीम का विश्वस्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने की भारत की क्षमता पर विश्वास बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।''

एनआरएआई के महासचिव पवनकुमार सिंह ने पीटीआई से कहा, ''यह ऐतिहासिक अवसर होगा जबकि भारत दो ओलंपिक कोटा प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा और हमें इस पर बहुत गर्व है। हम नयी दिल्ली में करणी सिंह रेंज में आईएसएसएफ विश्व कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन (21-30 अप्रैल) और राइफल एवं पिस्टल में एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''एशियाई चैंपियनशिप की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) ने प्रमुख प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी करने की हमारी क्षमताओं पर भरोसा दिखाया है। इससे निशानेबाजी में भारत के बढ़ते प्रभाव और आईएसएसएफ का हम पर

भरोसे का पता चलता है।''

सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत इन दोनों प्रतियोगिताओं का पूरा फायदा उठाकर अधिक से अधिक कोटा स्थान हासिल करेगा। आईएसएसएफ ने पेरिस ओलंपिक खेलों के चक्र के दौरान विश्व कप में ओलंपिक क्वालीफिकेशन कोटा नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों के चक्र के लिए कोटा स्थान देने का फैसला किया है।

सिंह ने कहा, ''उम्मीद है कि भारतीय निशानेबाज इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। हमारा लक्ष्य देश के लिए आवंटित सभी 24 स्थानों का कोटा हासिल करना है जो पेरिस ओलंपिक के लिए हासिल किए गए 22 कोटा स्थान से अधिक है।'' दिल्ली में बुधवार से इस वर्ष की एशियाई चैंपियनशिप (राइफल/पिस्टल) का आयोजन किया जाएगा। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग में 20 देशों के 300 से अधिक निशानेबाज भाग लेंगे।

आईसीसी क्रिकेट की भलाई के लिए निष्पक्ष रहते हुए फैसला ले : अफरीदी

लाहौर । पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने आईसीसी टी20 विश्वकप में इस बार भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं होने पर नाराजगी जतायी है । अफरीदी ने साथ ही कहा कि अब आईसीसी को इस मामले में निष्पक्ष रहते हुए कोई फैसला लेना चाहिये । अफरीदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब राजनीति संवाद के दरवाजे बंद कर देती है तो क्रिकेट दरवाजे खोल सकता है । यह दुखद है कि इस बार पाक टीम विश्वकप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी । साथ ही कहा कि वह अपनी सरकार के भारत के खिलाफ मैच से बाहर रहने के फैसले का समर्थन करते हैं । दोनो ही टीमों के बीच ये मैच 15 फरवीर को कोलंबो में होना था । अफरीदी के अलावा मोहम्मद यूसुफ और राशिद लतीफ, मोइन खान और सरफराज अहमद जैसे पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी सरकार के भारतीय टीम का बहिष्कार करने के फैसले का समर्थन किया है । लतीफ ने कहा, आईसीसी ने जिस तरह बांग्लादेश के साथ व्यवहार किया या हाल के वर्षों में जिस तरह वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने झुकी है, ऐसे में किसी न किसी को कठोर रूख अपनाने की जरुरत थी ।। मोइन ने कहा, अब आईसीसी को देखना होगा कि वह विश्व क्रिकेट के व्यापक हित में किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है । सरफराज ने कहा कि वह पाक टीम को भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति न मिलने के कारणों को समझ सकते हैं । वहीं पाक टीम के कप्तान सलमान अली ने कहा कि उनकी टीम विश्वकप में हार मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के इरादे से श्रीलंका जाएगी । उन्होंने कहा, हमारे तीन अन्य ग्रुप मैच हैं और हम सभी जीतकर अगले दौर के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे । पाकिस्तान टीम अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगी ।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, कहा- समंदर में तैनात है यूएस नेवी

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को फिर से धमकी दी है। तेहरान की बयानबाजी के बीच अमेरिका ने ईरान के आसपास सेना तैनात कर दी है। वहीं, डोनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील पूरी होने की उम्मीद जताई है। फ्लोरिडा में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने बेशक ईरान के पास सेना तैनात की है, लेकिन हम अभी भी कूटनीति के रास्ते हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डोनल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली जहाज हैं, जो ईरान के बेहद करीब हैं। अगर हम डील नहीं करते हैं, तो हमें पता लगाना होगा कि कहां कमी रह गई है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, हमारे पास काफी बड़े, शक्तिशाली जहाज हैं, जो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। वो डील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डील हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो देखते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ किया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने युद्ध शुरू किया तो इससे पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा।

2 साल के लिए बंद रहेगा कैनेडी सेंटर? ट्रंप ने दिया आदेश

वाशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह दो साल के लिए वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर को कंस्ट्रक्शन के लिए बंद कर देंगे। व्हाइट हाउस लौटने के बाद से यह इस मशहूर जगह को बदलने की दिशा में उनका ताजा कदम है। इस बात की घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्ताव को फर्स्ट लेडी पर बनी डॉक्यूमेंट्री मेलानिया के प्रीमियर के कुछ दिनों बाद केनेडी सेंटर के बोर्ड से मंजूरी मिलनी थी, जिसमें उनके चुने हुए सहयोगी भरे हुए हैं। ट्रंप खुद सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन हैं। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, कई बहुत सम्मानित एक्सपर्ट्स से मिले इनपुट के आधार पर लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला। एक थके हुए, टूटे-फूटे और खस्ताहाल सेंटर को, जो कई सालों से आर्थिक और स्ट्रक्चरल दोनों तरह से खराब हालत में था, उसे कला, संगीत और मनोरंजन का वर्ल्ड क्लास गढ़ बना देगा। न तो ट्रंप और न ही ट्रंप के सहयोगी केनेडी सेंटर के प्रेसिडेंट रिक ग्रेनेल ने बिल्डिंग के खराब हालत में होने के अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत दिया है। इस अचानक फैसले से निश्चित रूप से विरोध होगा क्योंकि ट्रंप इस लोकप्रिय जगह को बदल रहे हैं। यह एक नेशनल कल्चरल सेंटर के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन 1964 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद कांग्रेस ने इसका नाम बदलकर उनके लिए एक जीवित स्मारक कर दिया था। 1971 में खुला यह सेंटर, नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा सहित कलाओं के लिए एक पब्लिक शोकेस के तौर पर पूरे साल खुला रहता है।

लैपटॉप पर उंगलियां चलाता मर गया युवक! मौत के 8 घंटे बाद भी फोन पर मिलता रहा काम

बीजिंग, एजेंसी। चीन में 32 साल के एक प्रोग्रामर की लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद अचानक मौत हो गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस युवक का नाम गाओ गुआंगहुई था। उनके परिवार का कहना है कि उनकी मौत का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा काम (ओवरवर्क) था। इस घटना के बाद चीन के सोशल मीडिया पर काम के दबाव और निजी जिंदगी के संतुलन को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में प्रमोशन मिलने के बाद गाओ को टीम लीडर बनाया गया था। इसके बाद उनके लिए देर रात तक काम करना और ओवरटाइम करना आम बात हो गई थी। उनकी प पत्नी ली कई बार उनसे कहती थीं कि वह समय पर घर लौटें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ली ने भावुक होते हुए कहा, अगर मैं समय पीछे ले जा पाती, तो मैं उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देती। यह दुखद घटना 29 नवंबर 2025 की है। उस दिन सुबह गाओ ने उठते ही तबीयत खराब महसूस की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर से ही काम करना जारी रखा। कुछ समय बाद उनकी हालत और बिगड़ गई और वह अचानक बेहोश हो गए। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर में उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण अचानक दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) बताया गया। मौत के बाद भी आता रहा काम का मैसेज इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गाओ की मौत के आठ घंटे बाद भी उनके फोन पर काम से जुड़ा एक मैसेज आया। इसमें उनसे तुरंत एक जरूरी निरीक्षण करने के लिए कहा गया था। इस घटना ने चीन में काम के अत्यधिक दबाव वाले माहौल पर भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या नौकरी इंसान की जान से ज्यादा जरूरी है? हालांकि, चीन के श्रम कानून के अनुसार किसी कर्मचारी को दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 44 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए।

30 लाख से ज्यादा पन्ने, तस्वीरें और वीडियो... दुनिया में खलबली मचाने वाली है एपस्टीन फाइल्स?

वाशिंगटन, एजेंसी। जेफ्री एपस्टीन की फाइल्स एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार (30 जनवरी) को यौन अपराधी से जुड़े दस्तावेजों का एक नया सेट जारी किया है। फाइलों के इस नए सेट में कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था और जिनका संबंध दोषी सेक्स अपराधी से था।

गौर करने वाली बात यह है कि दस्तावेजों में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें से किसी पर भी एपस्टीन के संबंध में गलत काम करने का औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।

क्या हैं एपस्टीन फाइल्स : दरअसल, एपस्टीन फाइल्स अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एप्सटीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज हैं, जो उसकी यौन तस्करी और शोषण के मामलों से जुड़े हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने पारदर्शिता कानून के तहत इन्हें सार्वजनिक किया है। इन फाइल्स से जुड़े कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा पन्ने जारी किए गए हैं। इनमें 2 हजार से ज्यादा वीडियो और लगभग 1 लाख 80 हजार तस्वीरें शामिल हैं। हालांकि, पीड़ितों की सुरक्षा को देखते हुए कई हिस्से अभी भी छिपाए गए हैं।

कौन था जेफ्री एपस्टीन : एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था और उसने अमीर और ताकतवर लोगों से रिश्ते बनाए हुए थे। उसके ऊपर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे। जांच में पता चला है कि कई पीड़ित लड़कियां

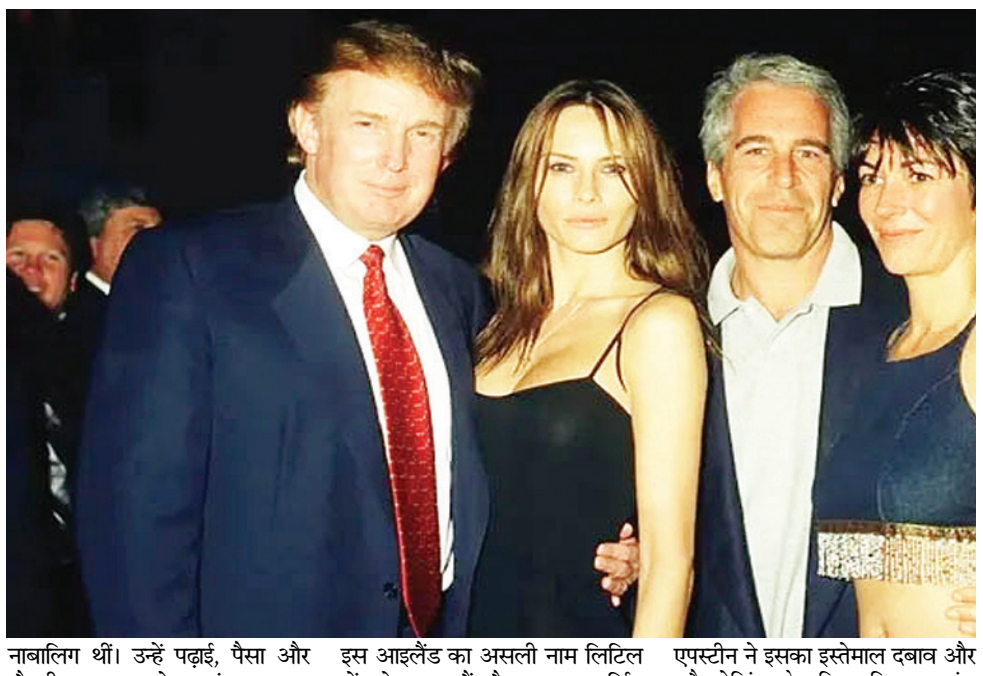

नाबालिग थीं। उन्हें पढ़ाई, पैसा और नौकरी का लालच देकर फंसाया गयाष फिर उनका यौन शोषण किया गया। इस मामले ने अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। 2008 में उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार भी किया गया। अपने मजबूत संबंधों के दम पर वह रिहा हुआ लेकिन 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इसी साल न्यूयॉर्क की जेल में उसे मृत पाया गया।

एपस्टीन आइलैंड : एपस्टीन फाइल्स के साथ-साथ एपस्टीन आइलैंड की भी जमकर चर्चा हो रही है। इस आइलैंड का असली नाम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है। यह यूएस वर्जिन आइलैंड्स में स्थित एक प्राइवेट द्वीप था। इस पर एपस्टीन ने कब्जा कर रखा था। पीड़ितों की अगर मानें तो इसी आइलैंड पर एपस्टीन ने कई अपराध किए और इसी वजह से इसे एपस्टीन आइलैंड कहा जाने लगा।

खेला गया ब्लैकमेलिंग का खेल : आरोप लगा है कि एपस्टीन ने अमीर, ताकतवर और मशहूर लोगों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनवाए। अपना काम निकलवाने के लिए एपस्टीन ने इसका इस्तेमाल दबाव और ब्लैकमेलिंग के लिए किया। जांच एजेंसियों को इससे संबंधित कई डिजिटल सबूत भी मिले हैं। हालांकि कई सबूतों को अभी भी गोपनीय रखा गया है।

किन लोगों के नाम सामने आए : एपस्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, वह पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मौजूदा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, एंड्रयू माउंटबेटन, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसी मशहूर हस्तियां शामिल हैं।

अब तक 200 बागियों की मौत, आग और बारूद का साया... धमाकों से दहला बलूचिस्तान

इस्लामाबाद , एजेंसी। जपाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात तेजी से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से पूरा इलाका हिंसा, धमाकों और सैन्य कार्रवाई की चपेट में है। शनिवार को बलोच विद्रोहियों के हमलों से हिले पाकिस्तान ने अब बड़े पैमाने पर जवाबी अभियान छेड़ दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षाबलों का दावा है कि करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन में 200 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराया गया है।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने क्वेटा में मीडिया को बताया कि यह आंकड़ा अलग-अलग छापेमारी और व्यापक तलाशी अभियानों में मारे गए लोगों को मिलाकर तैयार किया गया है। उनके मुताबिक यह आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है।

कई जिलों में एक साथ हमला, भारी जानमाल का नुकसान : इससे पहले बलूच विद्रोहियों ने एक साथ कई जिलों को निशाना बनाया था। क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग और नोश्की में हुए हमलों में 17 सुरक्षाकर्मी और 31 आम नागरिक मारे गए थे. हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इसके बाद सेना, पुलिस और आतंकवाद-रोधी बलों ने पूरे प्रांत में संयुक्त अभियान शुरू कर

दिया, जिसमें हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और स्पेशल यूनिट्स तैनात की गईं।

बिना सबूत भारत पर आरोप, नई दिल्ली ने किया खंडन : हिंसा के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी सेना और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है, हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं और नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए हर बार इसी तरह के आरोप लगाता है. उन्होंने कहा कि हिंसा की जड़ें बलूचिस्तान में लंबे समय से चली आ रही शिकायतों, दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ी हैं। इसी बीच बीएलए ने हिंसा और तेज करने का संकेत दिया है। संगठन ने ऐलान किया है कि उसने 'ऑपरेशन हेरॉफ' के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाएगा।

रूस का यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला, बस को बनाया निशाना, 15 लोगों की मौत

मास्को, एजेंसी। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूसी ड्रोन हमले में खनिकों को ले जा रही बस को निशाना बनाया गया जिसमें 15 लोग मारे गए। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने रविवार को यह जानकारी दी। आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, इस हमले में सात अन्य लोग घायल हो गए और कुछ जगह आग भी लग गई जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी डीटीईके ने कहा कि बस उसकी थी और उसने रूस पर निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में डीटीईके की खदानों पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला करने का आरोप लगाया। इस क्षेत्र की राजधानी निप्रो है। कंपनी ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा, हमलों में से एक का केंद्र कंपनी की एक बस थी जो निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में ड्यूटी पूरी होने के बाद कंपनी से खनिकों को ले जा रही थी।

अफगानिस्तान में 170 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद, दो गिरफ्तार : काबुल, एजेंसी। पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में पुलिस ने एक वाहन से 170 किलो अफीम और

हशीश बरामद की है। गुप्त जानकारी के आधार पर शनिवार को वाहन को रोका गया और खोज के दौरान मादक पदार्थ छिपे हुए पाए गए। वाहन में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कथित रूप से अवैध तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायिक अधिकारियों के हवाले किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि प्रांत में किसी को भी मादक पदार्थ का उत्पादन या तस्करी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले, खोस्त प्रांत में 18 किलो हशीश और जवज्जान व तख़ार प्रांतों में भी विभिन्न मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई अफगान अधिकारियों की अवैध ड्रग उत्पादन और तस्करी रोकने की निरंतर कोशिशों का हिस्सा है।

एपस्टीन फाइलों में नाम आने पर स्लोवाकिया के एनएसए का इस्तीफा, ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू पर भी दबाव

लंदन/वाशिंगटन, एजेंसी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री राबर्ट फिको के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जेफरी एपस्टीन से संबंधित नई फाइलों के सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिनमें पता चला है कि दोनों ने युवतियों के बारे में ईमेल का आदान-प्रदान किया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाजैक ने किसी भी प्रकार की गलती से इन्कार किया। उन्होंने इसे अनौपचारिक और हल्के-फुल्के अंदाज में ईमेल का आदान-प्रदान बताया।

आखिर क्यों दिया इस्तीफा : उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, ताकि इस स्थिति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए न किया जाए। फिको ने शनिवार को घोषणा की कि

उन्होंने लाजैक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन से संबंधित लाखों नई फाइलें शुक्रवार को प्रकाशित की थीं।

गवाही देने के लिए एंड्रयू पर बढ़ रहा दबाव : ब्रिटेन के विवादों में घिरे पूर्व राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर पर इस सप्ताहांत में अमेरिका की उस समिति के समक्ष गवाही देने का दबाव बढ़ रहा है जो यौन अपराध के दोषी जेफरी एपस्टीन के अपराधों की सीमा की जांच कर रही है। एक दूसरी महिला ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन उसे 2010 में तत्कालीन राजकुमार एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन ले गया था। यह मुलाकात विंडसर कैसल स्थित उनके रायल लाज आवास पर हुई थी।

कई शक्तिशाली लोगों के नाम शामिल : एपस्टीन फाइलों में कई शक्तिशाली लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें पूर्व राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन- विंडसर से लेकर एलन मस्क तक के नाम शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख नामों में वर्जिन ग्रुप के अरबपति संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन, न्यूयार्क जायंट्स के को-आनर स्टीवन टिश, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक आदि शामिल हैं।

बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ का कहर: बीएलए ने जारी की दो महिला हमलावरों की फोटो, ISI हेडक्वार्टर को बनाया था निशाना!

इस्लामाबाद एजेंसी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अशांत प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर दहल उठा है। प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ (ब्लैक स्टॉर्म) के दूसरे चरण के तहत पूरे प्रांत में समन्वित हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 17 सुरक्षाकर्मियों सहित लगभग 50 लोगों की जान जा चुकी है। इस बार के हमलों ने दुनिया का ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि इसमें महिला फिदायीन (आत्मघाती हमलावरों) का इस्तेमाल किया गया है। वहीं बीएलए ने दो महिला हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं जिनमें से एक की पहचान 24 वर्षीय आसिफा मेंगल के रूप में हुई है।

महिला हमलावर आसिफा

मेंगल : बीएलए ने दो महिला हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं जिनमें से एक की पहचान 24 वर्षीय आसिफा मेंगल के रूप में हुई है। नुश्की की रहने वाली आसिफा ने अपने 21वें जन्मदिन पर बीएलए की मजीद ब्रिगेड जॉइन की थी।जनवरी 2024 में उसने फिदायीन बनने का फैसला किया और शनिवार को नुश्की स्थित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ढ्स्ढ के मुख्यालय को निशाना बनाया। एक वीडियो संदेश में उसने बलूच नागरिकों से एकजुट होने और पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की है। ऑपरेशन हेरोफ और सेना का जवाब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच पिछले 40 घंटों से खूनी जंग जारी है। पाकिस्तान के कनिष्ठ मंत्री तलाल चौधरी के अनुसार, हमलावर नागरिक वेशभूषा में स्कूलों, बैंकों और अस्पतालों में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नुश्की, हब, चमन, नसीराबाद, ग्वादर और मकरान जैसे क्षेत्रों में एक साथ हमले किए गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने बताया कि अब तक 140 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना का दावा है कि उग्रवादियों के किसी भी शहर या रणनीतिक ठिकाने पर कब्जे की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है।

बलूचिस्तान में अशांति की वजह क्या है : बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा प्रांत है। यहां गैस और खनिजों का भंडार है लेकिन बलूच समूहों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और विदेशी कंपनियां (खासकर चीन) उनका शोषण कर रही हैं। बीएलए जैसे अलगावावादी समूह दशकों से पूर्ण स्वतंत्रता और संसाधनों में बड़े हिस्से की मांग को लेकर सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं।

2026 की GDP ग्रोथ में यूएस से आगे निकला भारत, एलन मस्क बोले- बदल रहा पावर बैलेंस

न्यूयार्क, एजेंसी। 31 जनवरी को वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्रेडिट देते हुए जारी की गई एक रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत, अमेरिका से आगे निकल गया है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स की पोस्ट को री-शेयर किया और लिखा, सत्ता का संतुलन बदल रहा है।

अमेरिका से आगे निकला भारत 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान के मामले में भारत को अमेरिका से आगे बताया गया है। दुनिया भर में होने वाले अनुमानित विस्तार में भारत का हिस्सा 17 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका 9.9 प्रतिशत पर है। आईएमएफ की जारी की गई रिपोर्ट में चीन सबसे आगे है। 2026 में चीन की जीडीपी ग्रोथ 26.6 प्रतिशत बताई गई है, जिसका मतलब है कि ये दोनों एशियाई अर्थव्यवस्थाएं मिलकर अब ग्लोबल तष्ठक्कग्रोथ का 43.6 प्रतिशत हिस्सा चला रही हैं। एलन मस्क भारत की तरक्की पर करीब से नजर रख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार मिल चुके हैं और भारत में अपनी कंपनी के लिए बेहतर जगह की तलाश कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने दोहराई मस्क की बात बजट 2026 पर यूथ डायलॉग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलन मस्क के पोस्ट को लेकर अपनी बात रखी। वित्त मंत्री ने कहा, एलन मस्क IMF के डाटा का हवाला देते हुए कहते हैं वाह, क्या यह सच है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, ग्लोबल तष्ठक्कग्रोथ में चीन का योगदान 26 प्रतिशत है। भारत का योगदान 17 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, ग्लोबल तष्ठक्कग्रोथ का 43 प्रतिशत इन दोनों इकोनॉमी से आता है।

खत्म कर देंगे भारत और चीन के बीच का गैप : वित्त मंत्री ने आगे कहा, लेकिन भारत के विपक्ष को भी यह समझना चाहिए कि यह उस तरह की ताकत है जो भारत ने अब हासिल की है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर, गैप बड़ा हो सकता है, 26 और 17, लेकिन हम इसे पाट देंगे। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, लेकिन हमें यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि, एक बड़ी इकोनॉमी के साथ, जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, हम ग्लोबल तष्ठक्कग्रोथ में 43 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ यूएस में आक्रोश, शिकागो से लॉस एंजिलिस तक सड़कों पर उतरे अमेरिकी हिंदू

ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लक्षित हमलों का विरोध करते हुए हिंदू अमेरिकियों ने लगभग दो दर्जन शहरों में शांतिपूर्ण रैलियां और प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं। उन्होंने अमेरिकी सांसदों और अंतरराष्ट्रीय निकायों से कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रिंसटन, लॉस एंजिलिस, शिकागो, बे एरिया, डेट्राइट और टैंपा सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। आयोजकों ने कहा कि समन्वित विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और जवाबदेही तय करना था। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में हुए एकत्रित प्रिंसटन में एक रैली में एक वक्ता ने कहा कि वे सभी बांग्लादेश में नरसंहार का सामना कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के समर्थन में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल से 3,000 से अधिक हमले हुए हैं। प्रदर्शनकारी ने मांग की, आवाज उठाने का समय आ गया है। इसे रोकने का समय आ गया है। डेट्राइट में प्रदर्शनकारियों ने इसे धीरे-धीरे हो रहा नरसंहार बताया और कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने समर्थकों से अपने सांसदों से संपर्क करने, स्थानीय स्तर पर एकजुट होने और वाशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। वाशिंगटन डीसी में नौ फरवरी को कांग्रेस की सुनवाई निर्धारित की गई है।

बांग्लादेश में राजनीतिक दमन और लक्षित हिंसा जारी, जेल में बंद अवामी लीग के नेता की मौत : ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली

अंतरिम सरकार के तहत राजनीतिक दमन और लक्षित हिंसा जारी है। अवामी लीग से जुड़े एक नेता की जेल में मौत हो गई। वहीं, एक कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। चटगांव में अवामी लीग के 70 वर्षीय नेता अब्दुर रहमान मिया की जेल में मौत हो गई। परिवार के सदस्यों के अनुसार, फेफड़ों के गंभीर कैंसर और कई अन्य समस्याओं के बावजूद उन्हें जमानत और पर्याप्त चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया। उन्हें 17 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, नरसिंगदी में 45 वर्षीय पूर्व छात्र लीग नेता अजीमुल कादर भुइयां का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। छात्र लीग, अवामी लीग का छात्र संगठन है। पार्टी नेताओं का दावा है कि हत्या में जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने किसी भी राजनीतिक मकसद की पुष्टि नहीं की है। दिनाजपुर में बीएनपी के चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के चुनाव प्रचार कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर हमला किया, कुर्सियां और मेजें तोड़ दीं और बैनर तथा चुनाव प्रचार सामग्री फाड़ दीं। हमले के दौरान कार्यालय में मौजूद दो बीएनपी कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया गया।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रील बनाने का जुनून बना काल, वंदे भारत की चपेट में आने से यूपी के दो युवकों की मौत

राजकोट (एजेंसी)। गुजरात के राजकोट में सोशल मीडिया के लिए रील और सेल्फी बनाने का जानलेवा शौक एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया। भक्तिनगर और रिबडा रेलवे स्टेशन के बीच मालधारी रेलवे फाटक के पास सोमवार दोपहर तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक रेलवे ट्रैक के बेहद करीब खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। हादसे का शिकार हुए तीनों युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और राजकोट की एक फैक्ट्री में मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते थे। मृतकों की पहचान संदीप पटेल और संदीप कोहरी के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक का नाम कपिल है, जिसकी हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। चश्मदीदों और पुलिस के अनुसार, वंदे भारत ट्रेन अपने निर्धारित रूट पर उच्च गति से गुजर रही थी, तभी ये युवक ट्रैक के पास रील बनाने और फोटो खींचने में मशगूल थे। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे सीधे उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक की मौत इलाज के दौरान हुई। घायल कपिल को तत्काल 108 एम्बुलेंस के जरिए राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए रेल यातायात भी बाधित रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। राजकोट दक्षिण के एसीपी भावेश जाधव ने बताया कि प्राथमिक जांच और चश्मदीदों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ है कि युवक ट्रेन के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक के पास सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन ने जनता से बार-बार अपील की है कि वे पटरियों के पास सेल्फी लेने या वीडियो बनाने जैसी खतरनाक गतिविधियों से दूर रहें। वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों के आने के बाद रेलवे ट्रैक के पास की गई छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है।

हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की बस खाई में गिरी, 3 की मौत, कई गंभीर रुप से घायल

देहरादून (एजेंसी)। देहरादून के विकासनगर इलाके में बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा क्वाणु इलाके में सुदोई खड्ड के पास हुआ, जब चौपाल-नेरवा से हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब जा रही हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस सुबह करीब 6:30 बजे चौपाल डिपो से नेहवा पहुंची थी और मीनस-क्वाणु-हरिपुर रूट से पांवटा साहिब की ओर जा रही थी। उस समय बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि मीनस-क्वाणु-हरिपुर सड़क पर सुदोई खड्ड के पास एक ट्रक को रास्ता देते समय सड़क का किनारा धंस गया। नतीजतन, यात्रियों से भरी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस का संतुलन बिगड़ गया, वह कई बार पलटी और आखिरकार सीधी गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों में मदद करने लगे। पुलिस प्रशासन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने जाजपुर के बिराजा मंदिर में पिंड दान किया

जाजपुर (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को ओडिशा के जाजपुर जिले स्थित बिराजा मंदिर में पिंड दान अनुष्ठान किया। इस पवित्र कार्यक्रम का उद्देश्य उनके पूर्वजों की आत्माओं के उद्धार के लिए धार्मिक संस्कार करना था। मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए लगभग 600 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा धार्मिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिंड दान के बाद वह बालासोर स्थित फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर वह विश्वविद्यालय परिसर में नए निर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी करेंगी। अधिकारियों के अनुसार यह पहल पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति का यह कार्यक्रम क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का क्षण भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्थानीय धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है।

नवी मुंबई की लापता लॉ स्टूडेंट श्रेया पाटी लोनावला में मृत मिली

मुंबई (एजेंसी)। नवी मुंबई से लापता 20 वर्षीय लॉ स्टूडेंट श्रेया नरेंद्र पाटी का शव पुणे जिले के लोनावाला स्थित टाइगर पॉइंट की 400 फीट गहरी खाई में मिला है। पुलिस के अनुसार, श्रेया 30 जनवरी से लापता थी। शव को ढूँढने में ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। श्रेया बिट्स लॉ स्कूल की छात्रा थी। 30 जनवरी को उसने नवी मुंबई स्थित घर से कहा था कि वह लोनावला में ड्यूक्स नोज पर ट्रेकिंग करने जा रही है और शाम तक लौट आएगी। इसके बाद उसका फोन नेटवर्क से बाहर हो गया। पुलिस ने बताया कि उसी दिन शाम को श्रेया के पिता को टाइगर पॉइंट के पास नाश्ते की दुकान चलाने वाले व्यक्ति का फोन आया। दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान के पास एक बैग मिला है, जिसमें श्रेया का कॉलेज आईडी कार्ड था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने लोनावला में खोजबीन तेज की और ड्रोन की मदद से उसका शव खाई में पाया। अधिकारियों का अनुमान है कि श्रेया खाई में गिर गई, लेकिन मामले की पूरी जांच अभी चल रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजकोट के यस बैंक में भीषण आग, कैश सुरक्षित, फर्नीचर जलकर खाक

राजकोट (एजेंसी)। गुजरात के राजकोट शहर के रेसकोर्स रिंग रोड स्थित यस बैंक की शाखा में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, और लगभग एक घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बैंक का पूरा फर्नीचर, 12 कंप्यूटर और प्रिंटर जलकर खाक हो गए हैं।

पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत ने व्यापारिक समझौतों की झड़ी लगा दी: रिजिजू

– ट्रेड डील के बाद एनडीए संसदीय बैठक में पीएम मोदी का तालियों से स्वागत

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर हुई चर्चा के बाद अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 25 से घटाकर 18फीसदी करने का ऐलान किया है। भारत-अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट के बाद मंगलवार को एनडीए संसदीय बैठक में पीएम मोदी का तालियों और तारीफों के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को मौजूदा 25 से घटाकर 18 फीसदी कर देगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक में कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत ने व्यापारिक समझौतों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक साख को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ, यूएई, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अब अमेरिका के साथ अहम व्यापारिक समझौते किए हैं। ये

समझौते न केवल भारत के प्रति दुनिया के भरोसे को दर्शाते हैं, बल्कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

रिजिजू ने बताया कि यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। भारत की पहचान और कद वैश्विक स्तर पर बढ़ा है और यह इन ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत पर कई देशों के भरोसे को दिखाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने इस डेवलपमेंट को भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया और इस फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग से अहम अवसर खुलेंगे और दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा।

पीएम मोमदी ने ट्रंप के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम है और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारतीय सामानों पर अपनी आपसी टैरिफ दर को 25 से घटाकर 18 फीसदी कर देगा और इस कदम को पीएम मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की संसद में सरकार दे पूरी जानकारी : मायावती

लखनऊ (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों के बाद अमेरिका द्वारा 18 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने को लेकर कहा कि इस फैसले का वास्तविक असर ज़मीन पर लागू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, इसलिए पर्याप्त जानकारी के अभाव में जल्दबाज़ी में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। सोशल मीडिया पर मंगलवार को जारी बयान में बसपा नेत्री मायावती ने आशंका जताई कि इस तरह के कदमों का प्रभाव देश के बहुजन, गरीबों, मज़दूरों, किसानों और महिलाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह जानना ज़रूरी है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों से आम जनता को क्या लाभ या नुकसान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर संसद सत्र के दौरान विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि देशवासियों को सही-सही तथ्य मिल सकें और पारदर्शिता बनी रहे। उनका कहना था कि सरकार द्वारा समय रहते स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने से भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा संभव हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों और व्यापारिक नीतियों का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था और रोज़गार पर पड़ता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर पहलू पर विचार कर जनता के हितों की रक्षा करे।

'इन्नोफेस्ट-2026' वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विद्या विहार, डिंडोली द्वारा दो दिवसीय वार्षिक उत्सव 'इन्नोफेस्ट-2026' का आयोजन किया गया। आयोजन ने 3,600 से अधिक आगंतुकों उपस्थित रहें। ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया की कार्यक्रम शैक्षणिक गहराई और रचनात्मक प्रतिभा का एक अनूठा संगम रहा। विद्यार्थियों ने अनेकों भाषाओं में अपने अभिनव प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। आयोजन का मुख्य आकर्षण 'आर्ट गैलरी' रही, जिसने अपनी अद्भुत कलाकृतियों से आगंतुकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी। प्रदर्शनी की जीवंतता को और बढ़ाते हुए प्री-प्राइमरी विंग के नन्हे बच्चों की 'असाधारण' व्यवहारिक गतिविधियों ने सभी का मन मोह लिया और प्रारंभिक शिक्षा के एक नए स्वरूप को जीवंत कर दिया। आयोजन में छात्रों ने ऊर्जा से भरपूर खेल प्रदर्शन और संगीत के साथ-साथ क्लासिक एवं वेस्टर्न डांस प्रस्तुत किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त की चेतावनी पर बोलीं ममता- वे सरकार के पिछलग्गू की तरह काम कर रहे

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच भारी गहमागहमी देखने को मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि देश में कानून का शासन सर्वोपरि रहेगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आए तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कड़े लहजे में कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आयोग ने साफ किया कि वह अपने पास निहित शक्तियों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करेगा और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी ने आयोग पर सरकार का पिछलग्गू होने का आरोप लगाया है।

यह विवाद राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष मतदाता सूची से संबंधित कई गंभीर मुद्दे उठाए। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान माहौल उस समय

तनावपूर्ण हो गया जब मुख्यमंत्री ने जाते समय मेज थपथपाकर अपनी बात रखी। आयोग के साथ हुई इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने निर्वाचन सदन से बाहर आकर चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आयोग पर राज्य के लोगों को निशाना बनाने और सत्तारूढ़ दल के पिछलग्गू की तरह काम करने का संगीन आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने इस बैठक को अपमानजनक करार देते हुए इसके बहिष्कार का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान लगभग 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। बनर्जी का आरोप है कि नाम की वर्तनी में मामूली बदलाव जैसी छोटी-छोटी बातों को आधार बनाकर मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है और प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले ही सरकार चुन लेगा? उन्होंने आयोग के व्यवहार को अहंकारी बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी को न्याय नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने आयोग को पांच पत्र भेजे थे, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग सत्ताधारी दल के निर्देशों पर काम कर रहा है। बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह लाखों लोगों को दिल्ली लाकर किसी के भी सामने उनकी परेड करा सकती हैं। उन्होंने बैठक से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें अंततः बैठक का बहिष्कार करना पड़ा। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर भी बंग भवन की घेराबंदी करने का आरोप लगाया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और बंग भवन में न तो सुरक्षा में कोई चूक हुई है और न ही किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव आयोग और एक राज्य की मुख्यमंत्री के बीच इस तरह का सीधा टकराव आने वाले चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा सकता है।

लव जिहाद से जुड़े बड़े रैकेट का खुलासा... हिंदू बताकर 300 लड़कियों को ब्लैकमेल कर देह व्यापार में धकेला

पुलिस ने मुख्य आरोपी अजफरुल हिस्ट्रीशीटर अपराधी को जेल भेजा

बस्ती (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लव जिहाद से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। आरोप है कि मुख्य आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके गिरोह ने 100 से अधिक लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया है। आरोपी अजफरुल खुद को हिंदू बताकर, कलावा पहनकर और शादी व नौकरी का झांसा देकर भरोसा जीतता था। इसके बाद में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पीड़िताओं को ब्लैकमेल कर उन्हें देह व्यापार में धकेल देता था। पीड़िताओं को नेपाल सहित देश के अलग-अलग राज्यों में भेजने का आरोप है। विरोध करने पर उनके परिवार को प्रताड़ित और अपहरण की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

पीड़िता बस्ती शहर में एक निजी हॉस्पिटल में काम करती थी, जहां जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई जो खुद को हिंदू बताकर अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने के नाम पर उसका मोबाइल नंबर ले लिया। धीरे धीरे आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया। युवती को शक न हो इसके लिए युवक अजफरुल बाकायदा अपने हाथ में कलावा पहनता था। भरोसा जीतकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी का झांसा दे लगातार दुष्कर्म किया। जब बात हद से ज्यादा गुजर गई और युवती शिकायत लेकर उसके घर पहुंची, तब घर में भी युवक ने अपने भाई व सहयोगी के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं पीड़िता यदि आरोपी के पास नहीं जाती थीं तब उसके भाई को भी किडनैप किया जाता था। पीड़िता के अनुसार आरोपी अजफरुल हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और इसके काले कारनामों में उसके घर वाले भी साथ देता है। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी और उसका भाई हिंदू बनकर करीब 300 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन सभी का आपत्तिजनक वीडियो बना चुके थे और उसके बाद देहव्यापार के लिए देश विदेश में बेच देते थे।

धोखाधड़ी की सुनियोजित साजिश

पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड हिस्ट्रीशीटर अपराधी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस है। अपनी असली पहचान छिपाकर वह खुद को प्रिंस (हिंदू) बताता था। युवतियों को गुमराह करने के लिए वह बाकायदा कलाई पर कलावा पहनता था, ताकि किसी को उसकी धार्मिक पहचान पर शक न हो। डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के दौरान जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कई बीजेपी विधायक दिल्ली पहुंचे, मणिपुर में सरकार बनाने की भागदौड़ तेज

–पार्टी ने तरुण चुक को बनाया पर्यवेक्षक, मैतेई समुदाय का बन सकता है सीएम

नई दिल्ली(एजेंसी)। बीजेपी में मणिपुर से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ तेज हो गई है। मणिपुर के 20 से ज्यादा बीजेपी विधायक दिल्ली पहुंचे थे और अब पार्टी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। राज्य में अगले साल राष्ट्रपति शासन खत्म होने वाला है और उससे पहले पार्टी के नेता चाहते हैं कि सरकार बना ली जाए। सोमवार को बीजेपी ने मणिपुर में पर्यवेक्षक के तौर पर तरुण चुग को नियुक्त किया है, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब किसी भी दिन मणिपुर में एनडीए विधायकों की बैठक हो सकती है जिसमें नेता का चुनाव हो सकता है।

बीजेपी सूत्रों का कहना है कि नई सरकार में राज्य में एक डिप्टी सीएम भी होगा। मैतेई समुदाय से सीएम बनने की संभावना है तो वहीं कुकी समुदाय के किसी नेता को डिप्टी सीएम के तौर पर

जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा इसलिए ताकि राज्य में यह संदेश जाए कि सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है।

बता दें बीते सालों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच तनाव देखा गया था और भीषण हिंसा हुई थी। इसी स्थिति से बचाव के लिए बीजेपी अब कुकी समाज से एक डिप्टी सीएम बना सकती है। बीरेन सिंह की सरकार में असेंबली स्पीकर रहे सत्यब्रत सिंह और पूर्व मंत्री टीएच बिस्वजीत सिंह और के गोविंद दास को मौका मिल सकता है। ये सभी नेता मैतेई समुदाय के ही हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर भी तनाव की स्थिति है। कुकी विधायकों का कहना है कि उनके समुदाय का दबाव है। ऐसी स्थिति में यदि कुकी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उनके लिए सरकार का हिस्सा बनना मुश्किल होगा। ऐसी मांग कुकी विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व से की है। इसको लेकर सरकार अब विचार कर रही है। यही नहीं कुछ विधायकों का कहना है कि मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश ही बना देना चाहिए, जिसकी अपनी विधानसभा भी हो। बता दें मणिपुर में पहली बार 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह 6 महीने के लिए था और फिर अगस्त 2025 में एक बार फिर से इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। एन बीरेन सिंह ने बीते साल फरवरी में सीएम पद छोड़ दिया था। मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। ऐसे में विधायक चाहते हैं कि कम से कम एक साल के लिए ही नए सिरे से सरकार का गठन किया जाए और कुछ काम करके ही जनता के बीच चुनाव में जाया जाए। फिलहाल 60 सीटों वाले मणिपुर सदन में बीजेपी के 37 विधायक हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: विकास की दौड़ में पटना सबसे आगे

पटना(एजेंसी)। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों ने राज्य के भीतर आर्थिक समृद्धि और विकास की गहरी विषमता को उजागर कर दिया है। सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि जहां राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 76,490 रुपये तक पहुंच गई है, वहीं जिलों के बीच विकास का असंतुलन चिंता का विषय बना हुआ है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय, ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की खपत, एलपीजी उपयोग और लघु बचत जैसे संकेतकों पर आधारित है, जो स्थानीय स्तर पर जीवन स्तर के वास्तविक अंतर को दर्शाती है।

सर्वेक्षण के अनुसार, राजधानी पटना ने राज्य के सबसे समृद्ध जिले के रूप में अपना दबदबा बरकरार रखा है। पटना में प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपये दर्ज की गई है, जो न केवल राज्य के औसत से कहीं अधिक है, बल्कि सबसे गरीब जिले की तुलना में लगभग छह गुना ज्यादा है। पटना की इस समृद्धि का मुख्य कारण वहां का व्यापारिक ढांचा, शैक्षणिक केंद्र और सरकारी सेवाओं की सघनता है। समृद्धि के मामले में बेगूसराय 61,566 रुपये की आय के साथ दूसरे और औद्योगिक गतिविधियों वाला मुंगेर 54,469 रुपये के साथ तीसरे स्थान पर खड़ा है।

इसके विपरीत, राज्य के कुछ जिले आज भी भीषण आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। शिवहर बिहार का सबसे गरीब जिला बनकर उभरा है, जहां प्रति व्यक्ति आय महज 22,047 रुपये है। इसी श्रेणी में अररिया (23,670 रुपये) और सीतामढ़ी (24,332 रुपये) का स्थान आता है। इन जिलों में आजीविका का मुख्य आधार कृषि है, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़, संसाधनों की कमी और औद्योगिक निवेश के अभाव ने यहां विकास की गति को रोक दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन पिछड़े जिलों में ईंधन और एलपीजी की खपत भी सबसे कम दर्ज की गई है, जो बुनियादी सुविधाओं की कमी की ओर इशारा करती है। हालांकि, व्यापक स्तर पर बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2024-25 में 13.1 प्रतिशत की शानदार विकास दर दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत 9.8 प्रतिशत से काफी बेहतर है। राज्य की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है, लेकिन कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी बजट आवंटित किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पिछड़े जिलों के लिए लक्षित औद्योगिक नीतियां और बाढ़ नियंत्रण के ठोस उपाय नहीं किए जाते, तब तक यह विषमता दूर करना संभव नहीं होगा। यह सर्वेक्षण नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है कि तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ समावेशी

विकास पर ध्यान देना अब अनिवार्य हो गया है।